प्रभात

इस अंक में ......

★ श्रद्धांजली ... 8
★ श्रमिक एलगार की 'समाज सेवा' ... 11
★ बजट 2003-04 पर एक टिप्पणी ... 12
★ केरल में जलियांवाला बाग ... 15
★ पेट्रोल का इंजेक्शन ... 18
★ सीआरपी के खिलाफ प्रतिरोधी संघर्ष ... 19
★ बिहार-झारखण्ड में पीजीए के हमले ... 25

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्स वार] दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष - 16 अंक - 2 अप्रैल - जून 2003 सहयोग राशि - 10 रुपए

इराक पर अमेरिकी दुराक्रमण - मानवता पर बर्बर हमला

21वीं सदी के हिटलर जॉर्ज बुश और 21वीं सदी के मुस्सोलिनी टोनी ब्लेयर की अगुवाई में 20 मार्च 2003 को इराक पर मानव इतिहास में अब तक का भयानक युद्ध छेड़ दिया गया। एक बेलगाम महाशक्ति अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए किस अमानवीय सीमा तक जा सकती है इसका जीता-जागता उदाहरण है यह युद्ध। 'इराक के पास सामूहिक विनाशक हथियार मौजूद हैं', 'सद्दाम हुस्सेन एक निरंकुश तानाशाह है जिससे विश्व को, खासकर अमेरिका को खतरा है', 'सद्दाम हुस्सेन के साथ अल क़ायदा का रिश्ता है', 'सद्दाम हुस्सेन लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है', आदि आरोप लगाते हुए अमेरिकी साम्राज्य-वादियों ने एक कमजोर व लगातार चल रहे युद्धों से जर्जर हो चुके एक गरीब देश पर भीषण बमबारी करके हजारों मासूम लोगों को हताहत कर दिया और भयानक तबाही मचाई। इराक पर हमला करके अमेरिका और उसके अनैतिक मित्र ब्रिटेन ने विश्व इतिहास में सबसे अधिक अन्यायपूर्ण और अलोकप्रिय युद्ध किया। दुनिया भर में कोने-कोने से इस युद्ध के खिलाफ लाखों जनता द्वारा विरोध के स्वर बुलन्द किए जाने के बावजूद और दुनिया के कई देशों के विरोध के बावजूद, बुश और ब्लेइर ने इस दरिन्दगी को अंजाम दिया। और इसे नाम दिया गया 'आपरेशन इराकी फ्रीडम', यानी इराक को 'आजादी' दिलवाने का अमेरिकी अभियान!

इस बच्चे का क्या कसूर था? अमेरिकी मिसाइल ने इस्माइल अब्बास (12) के हाथ ही नहीं काटे, बल्कि उसके माता-पिता और भाई की जान भी ली !

'आपरेशन इराकी फ्रीडम' की पृष्ठभूमि

पूरी दुनिया को अब यह साफ तौर पर मालूम हो गया कि इराक पर हमला करने का फैसला अमेरिका काफी पहले ही ले चुके थे और वे वहां अपने इशारों पर चलने वाली एक कठपुतली सरकार को गठित करेंगे। लेकिन इस नंगे दुराक्रमण के बचाव में उन्होंने अपने टुकड़ों पर पलने वाले कठपुतली मीडिया के माध्यम से पहले से ही यह प्रचारित किया कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियारों का जखीरा है जिससे दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इस तर्क को कई लोगों ने रद्द कर दिया। इससे उन्होंने राष्ट्र संघ के जरिए पिछले साल अक्टूबर में इराक में हथियारों की जांच शुरू करवा दी। राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य, खासकर फ्रान्स, चीन और रूस एकतरफा सैन्य कार्यवाही के पक्ष में नहीं थे। जर्मनी और अरब लीग के देशों ने भी

28 जुलाई - शहीद दिवस जिन्दाबाद !

अमेरिकी कार्यवाही का विरोध किया। हथियारों की जांच करने वाली टीम की रिपोर्ट भी अमेरिका के अनुकूल नहीं थी। उसने स्पष्ट कर दिया कि हथियारों की जांच के काम में इराकी सरकार ने पूरा सहयोग दिया। इससे ये साम्राज्यवादी डाकू बेचैन हो उठे क्योंकि युद्ध की उनकी तैयारियों में खलल-सी पड़ने लगी थी। उन्हें डर भी था कि युद्ध छेड़ने में देर हो जाए तो आने वाले महीनों में पड़ने वाली रेगिस्तानी गर्मी को उनके सैनिक झेल नहीं पाएंगे। इससे उन्होंने बिना देर किए सुरक्षा परिषद में धमकी, धौंस और बांह-मरोड़ के हथकण्डे भी अपनाकर बहुमत हासिल करने की घिनौनी कोशिश की। लेकिन फ्रान्स और रूस ने इराक पर युद्ध के लिए इजाजत देने के प्रस्ताव का वीटो करने का ऐलान कर दिया।

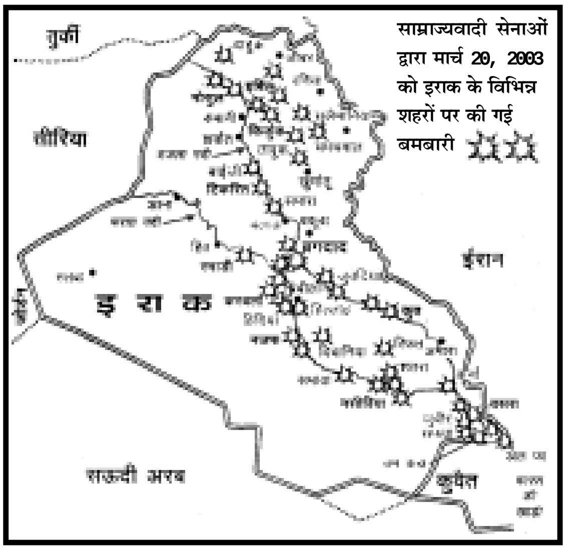

कुल 15 सदस्य देशों वाले सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित होने के लिए कम से कम 9 देशों का समर्थन जरूरी है। लेकिन उसे सिर्फ बुलगारिया का ही समर्थन हासिल हुआ था। अंगोला, कामेरून, चिली, मेक्सिको और पाकिस्तान किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके। जर्मनी, चीन और सिरिया ने फ्रान्स और रूस का समर्थन किया। इससे आखिरकार 17 मार्च को अमेरिका और उसके सहयोगी ब्रिटेन व स्पेइन ने अपना प्रस्ताव वापिस लिया। बाद में इन डकैतों ने अजोर्स नामक एक सुदूर द्वीप में गुप्त बैठक करके, ताकि विश्व जनता के विरोध से बचा जा सके, सद्दाम हुस्सेन को 48 घण्टे का अल्टिमेटम दिया कि वह या तो अपने परिवार के साथ देश छोड़कर चले जाए या फिर युद्ध झेले। जापान ने इस अल्टिमेटम का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन होवार्ड ने इस युद्ध में भाग लेने का ऐलान किया। लेकिन ये साम्राज्यवादी डकैत अपनी बात पर भी टिके नहीं रहे। उन्होंने 48 घण्टे की समय-सीमा के पहले ही, सद्दाम हुस्सेन के देश छोड़कर जाने की स्थिति में भी हमला करने का ऐलान किया। और इस तरह शुरू हो गया 'आपरेशन इराकी फ्रीडम' यानी इराक को 'आजादी' दिलवाने का अभियान।

इराक को 'आजादी' दिलवाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक, यानी 14 दिनों में ही कोई 20 करोड पाउण्ड (1 पाउण्ड = लगभग 453 ग्राम) बम गिराए गए जोकि इतिहास में ही अभूतपूर्व था। साम्राज्यवादी गठबन्धन सेना ने हजारों टन बम गिराकर हजारों जनता को मारने के अलावा रिहायशी इलाकों, ऐतिहासिक स्थलों, अनाज के गोदामों, बिजली के यंत्रों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, पानी के यंत्रों, आदि को तबाह कर दिया। राष्ट्र संघ ने इस भयानक तबाही का मौन साधकर समर्थन दिया।

सामूहिक विनाशक हथियार इराक के पास? या अमेरिका के पास?

अमेरिका-ब्रिटेन के गठबन्धन ने युद्ध के मुख्य कारण के रूप में इस तथाकथित तथ्य को पेश किया कि इराक के पास नरसंहार के जैविक तथा रासायनिक हथियार थे, अतः उन्हें नष्ट करने के लिए इराक पर हमला करना जरूरी हो गया था। अब जबकि अमेरिका के मुताबिक 'इराकी आजादी अभियान' समाप्त हो चुका है, लेकिन इराक में एक भी समूहिक विनाश का हथियार उन्हें हाथ नहीं लगा। काश! इराक में इन हथियारों को खोज निकालने के पहले अमेरिका वहां उनका रोपण किया होता!

सच तो यह है कि नरसंहार के आणविक, जैविक व रासायनिक हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा खुद अमेरिका के पास है, जिससे वह सम्पूर्ण मानवजाति को सात बार खत्म कर सकता है। इस तरह उसका कोई नैतिक अधिकार ही नहीं बनता कि दूसरों पर सामूहिक विनाश के हथियार रखने का आरोप लगाए। इस तर्क को छोड़ भी दिया जाए तो अमेरिका के आरोप में रत्ती भर भी सचाई नहीं है, आज इराक की चप्पा-चप्पा जमीन पर हमलावर सेनाओं का अधिकार है, न तो तीन सप्ताह के युद्ध में सद्दाम शासन

बम से बने गढ्ढों में ही खुद को छिपाने की विवशता

ने अपनी रक्षा हेतु रासायनिक एवं जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया और न ही अपनी पूरी कोशिश के बावजूद गठबन्धन की फौजें तथा उनकी गुप्तचर एजेन्सियां ऐसे हथियारों को खोज निकालने में कामयाब हो सकीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इराक के पास ये हथियार नहीं थे, हथियारों का होना अमेरिकी प्रचार तंत्र (मीडिया) का करिश्मा था। इसकी पुष्टि इराक में हथियार निरीक्षक दल के प्रमुख ब्लिक्स की इस आत्मस्वीकृति से भी होती है कि अमेरिकी सरकार ने भ्रमित एवं गुमराह करने वाली सूचनाएं उनको उपलब्ध कराईं।

विडम्बना यह है कि जिस देश के पास नरसंहार के हथियार होने के बहाने अमेरिका ने यह हमला किया, उसी देश पर उसने भयकंर बमबारी से और तरह-तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दी। इनमें ऐसे हथियार भी थे जिन्हें सामूहिक विनाश की श्रेणी में बताए जा सकते हैं। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका ने 1,000 क्रूइज मिसाइलें (जिनकी मारक क्षमता हिरोशिमा पर गिराए गए एटम् बम से अधिक थी) दागीं। इस युद्ध में अमेरिका ने क्लस्टर बम, डैजीकट्टर, क्रूड बम, बंकर बस्टर, डिप्लेटेड यूरेनियम आदि को खुलकर आजमाया। क्लस्टर बम तो एक ऐसा बम है जिसके विस्फोट से बिखरने वाले अनगिनत टुकड़े आने वाले कई सालों तक विस्फोटित होते रहेंगे और लोगों को हताहत करते रहेंगे। और डैजीकट्टर व क्रूड बमों को परमाणु बम के बाद सबसे घातक बम माने जाते हैं। डिप्लेटेड यूरेनियम एक ऐसा रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसका प्रभाव परमाणु बम के प्रभाव से कम नहीं होगा। इसके पहले 1999 में उसने युगोस्लोविया में भी इसका प्रयोग किया जिससे खुद गठबन्धन सेना के कई सैनिक घातक बीमारियों का शिकार बने थे। लेकिन अमेरिका हमेशा इसके प्रयोग के बारे में सचाई पर परदा डालने की कोशिश करता रहा है।

इराकी गणराज्य (अल जम्हूरिया अल इराकिया)

राजधानी :	बगदाद
क्षेत्रफल :	1 लाख 68 हजार वर्ग मील
सीमाएं :	पश्चिम में जोर्डान व सिरिया; उत्तर में तुर्की; पूर्व में ईरान; और दक्षिण में कुवैत और साउदी अरब
जनसंख्या :	2 करोड़ 12 लाख (1995 का अनुमान)
राष्ट्रीयताएं :	अरब 75-80% और कुर्द 15-20% और कुछ तुर्कमन
धर्म :	मुस्लिम 97% (शिया 60-65% और सुन्नी 32-37%)
भाषाएं :	अरबी (अधीकृत) और कुर्द
शिक्षा :	साक्षरता (1993) - 58%; 6-12 के आयु वर्ग को मुफ्त व आवश्यक शिक्षा
उद्योग :	कपड़े, पेट्रो केमिकल्स, तेल शुद्धीकरण, सिमेन्ट
फसलें :	गेंहू, चावल, खजूर और कपास
खनिज :	तेल और गैस

इसके पहले भी अमेरिका ने सामूहिक विनाश के हथियारों का खुलकर प्रयोग किया था। 1962-71 के बीच उसने वियतनाम पर कई अमानवीय हमले किए थे ताकि वह कम्युनिस्टों के हाथों में चला न जाए। उन हमलों में उसने नापाम बमों के अलावा 1 करोड़ 20 लाख टन एजेन्ट ऑरेन्ज (इसमें डयाक्सिन होता है) गिरा दिया। एजेन्ट ऑरेन्ज के दुष्प्रभाव से न सिर्फ वियतनामी लोगों के नाड़ीमण्डल को क्षति पहुंची बल्कि दमे की दीर्घकालिक शिकायत, दिल की बीमारियां, थैराइड सम्बन्धी बीमारियां, कोख में ही शिशुओं की विकलता, आंखों में मोतियाबिन्दु, आदि कई बीमारियों से लोगों का जीना ही मुश्किल हो चुका था। इसके अलावा उसने सरिन नामक जहरीला गैस का भी प्रयोग किया था।

अमेरिकी साम्राज्यवादी इतने कायर हैं कि उन्होंने इराक पर तभी यह युद्ध छेड़ दिया, जब वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि उसके पास ऐसा कोई बड़ा हथियार नहीं है जिससे वह उनका मुकाबला कर सके। इराक के पास मौजूद 40 अल समौद मिसाइलों को राष्ट्र संघ के जरिए नष्ट करवाने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि अब इराक शस्त्रास्तों की दृष्टि से पूरी तरह पंगु बन गया। हालांकि इस तथ्य से भी आंख बन्द नहीं की जा सकती है कि सद्दाम के पास रासायनिक व जैविक हथियार ईरान-इराक युद्ध के समय थे और यह हथियार किसी और ने नहीं, बल्कि अमेरिका ने ही दिए थे। उस समय सद्दाम उसका दोस्त था। दोस्त सद्दाम हथियार रख भी सकता है और उनका इस्तेमाल भी कर सकता है, जबकि दुश्मन सद्दाम हथियार न रखने पर भी हथियार रखने के आरोप में हमले का शिकार बन जाता है, यह एक विचित्र प्रकार की अमेरिकी नैतिकता है जिसकी कोई सानी नहीं।

क्या सद्दाम एक निरंकुश तानाशाह था?

अमेरिका का एक और आरोप यह है सद्दाम एक निरंकुश तानाशाह है जिससे विश्व समुदाय को बड़ा खतरा है। अगर सद्दाम वाकई एक तानाशाह होगा तो उसे गद्दी से उतारने का जिम्मा इराकी जनता का है, न कि अमेरिका का। दुनिया भर में कई तानाशाहों की मदद करके उनके जरिए लाखों लोगों का कत्लेआम करवाने के लिए बदनाम अमेरिका का यह कहना कि 'सद्दाम बड़ा तानाशाह है' जैसे भूत के मुंह से वेदपाठ है। अब जरा इस पर गौर किया जाए कि सद्दाम को तानाशाह किसने बनाया था।

चालीस साल पहले, जब जॉन एफ केन्नेडी अमेरिका का राष्ट्रपति था, सीआईए ने बाग्दाद में तख्तापलट की हिमायत की थी। 1963 में तत्कालीन सरकार को अपदस्थ कर बाथ पार्टी ने सफलतापूर्वक सत्ता हथिया ली थी। सीआईए द्वारा दी गई सूचियों की मदद से बाथ सरकार ने उन सैकड़ों डाक्टरों, अध्यापकों, वकीलों, राजनीतिकों का सुनियोजित ढंग से कत्लेआम किया जिन पर कम्युनिस्ट होने का संदेह था। बुद्धिजीवियों की एक पूरी पीढ़ी का ही सफाया कर दिया गया था। बताया जाता है यह कत्लेआम युवा सद्दाम हुस्सेन की, जो सीआईए का लाड़ला था, निगरानी में हुआ था। 1979 में बाथ पार्टी के भीतर पनपी गुटबाजी के चलते सद्दाम हुस्सेन इराक का राष्ट्रपति बन गया। 1980 में जब वह शिया मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा था, तब अमेरिका ने कहा था कि इराक के हित ही अमेरिका के हित हैं। वाशिंगटन और लन्दन ने सद्दाम हुस्सेन का खुलेआम और सीधे तौर पर समर्थन किया था। उन्होंने सद्दाम को पैसा, औजार और हथियार उपलब्ध करवाए थे। उन्हें दोहरे उपयोग वाली सामग्रियां भी दीं ताकि उनसे सामूहिक विनाश के हथियार बनाए जा सकें। उनके क्रूर अत्याचारों में अमेरिकियों की आर्थिक, नैतिक व पादार्थिक मदद थी।

ईरान के खिलाफ लगभग आठ साल तक चले लम्बे युद्ध में भी उन्होंने सद्दाम का समर्थन किया था। 1988 में हलाबजा में कुर्द जनता को जहरीले गैस के प्रयोग करके मारने में अमेरिकियों को

भागते इराकी जो भीषण बमबारी और गोलीबारी से खुद को बचाने कर रहे

मिली थी। इज्राएल द्वारा आए दिन की जा रही फिलिस्तीनियों की हत्याओं को भी अमेरिका का पूरा समर्थन मिला हुआ है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। दुनिया भर में तानाशाहों को पालने-पोसने वाला अमेरिका इराक पर अपने हमले को जायज ठहराने के लिए यह प्रचारित कर रहा है कि सद्दाम बड़ा तानाशाह है। सवाल यह नहीं कि वाकई सद्दाम एक खतरनाक तानाशाह था या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि अमेरिका को किसी दूसरे व्यक्ति को तानाशाह ठहराकर उसके देश पर हमला करने का अधिकार किसने दिया। सद्दाम की तानाशाही से लड़ना और उससे मुक्ति पाना इराकी जनता का काम है, न तो अमेरिका का और न ही, यहां तक कि, राष्ट्र संघ का।

कोई गलती महसूस नहीं हुई। अब, चौदह बरस बाद, अमेरिका इन्हीं अपराधों को खोद निकालकर इराक पर अपने हमले के लिए कारण बताकर अपनी कार्यवाही को न्यायोचित ठहराने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि पहले खाड़ी युद्ध के बाद बस्त्रा में हुई शिया मुसलमानों की बगावत की भी 'मित्र' देशों ने अनदेखी की। जब सद्दाम हुस्सेन उस बगावत को कुचल रहा था और बदले की भावना से हजारों लोगों का कत्लेआम कर रहा था, तब इन्होंने चुप्पी साध ली थी। अगर इन सारे सामूहिक नरसंहारों के लिए सद्दाम हुस्सेन को सजा देनी है, तो सबसे पहले उसके इन अत्याचारों का समर्थन करने वालों को, यानी अमेरिका और उसके गुर्गों को सजा देनी चाहिए।

तानाशाहों का तानाशाह और विश्व जनता का नम्बर एक दुश्मन अमेरिका ही

इतिहास गवाह है, मानवजाति के खिलाफ दुनिया में अब तक हुए घोरतम अपराधों के लिए खुद अमेरिकी साम्राज्यावाद ही जिम्मेदार है। दुनिया के कुख्यात तानाशाहों का अमेरिका ने समर्थन ही नहीं किया, बल्कि जनता के कत्लेआम करने में उनकी हर प्रकार की सहायता भी की। इसके अनेक उदाहरण हैं। वह अमेरिका ही था जिसने 1973 में लातिन अमेरिकी देश चिली में साल्वेडार अलेन्डी की तख्तापलट करके तानाशाह फिनोचेट को गद्दी पर बिठाया था। फिनोचेट के शासन काल में चिली में 10 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया था, जो अमेरिका की शह पर ही हुआ था। अमेरिका ने इन्डोनेशिया में सुहार्तो की तानाशाही का भी सक्रिय समर्थन किया जिसने 10 लाख से ज्यादा कम्युनिस्टों का कत्लेआम किया था। फिलिप्पीन्स के तानाशाह मार्कोस को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, जिसने देश में तमाम जनवादी अधिकारों का हनन किया था; सैकड़ों-हजारों लोगों की हत्या की थी; और देश की काफी सम्पदा लूट ली थी। जैरे के तानाशाह मोबुतु को अमेरिका का सहयोग मिला हुआ था जिससे उसने देश को अन्धाधुन्ध लूटा और बेहद अत्याचार किए थे। एक डुवेलियर, एक बाटिस्टा, एक बोथा, एक नोरीगा, एक फुजीमोरी.... तानाशाहों की यह सूची काफी लम्बी है जिन्हें अमेरिका की सक्रिय मदद

संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवक भूमिका

इराक युद्ध के दौरान राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने एक मंजे हुए अमेरिकी दलाल की तरह काम किया। इराक में मौजूद राष्ट्र संघ के सैकड़ों हथियार निरीक्षकों और कुवैत की सीमा में मौजूद शांति सेनाओं को तुरन्त वापिस बुलाया ताकि अमेरिका को इराक में घुसकर मनमाने ढंग से बमबारी करने में सुविधा मिल सके। इराक को निशस्त्र बनाकर अमेरिकी महाशक्ति के सामने उसे पूरी तरह से कमजोर बनाने की साजिश करके राष्ट्र संघ ने बेहद घिनौनी व निंदनीय भूमिका अदा की। उसने इराक को अपने अल समौद मिसाइलों को नष्ट करने पर बाध्य किया क्योंकि उनकी मारक दूरी 180 किलोमीटर है जोकि अंतर्राष्ट्रीय डकैतों द्वारा निर्धारित दूरी से 30 किलोमीटर ज्यादा है। 1991 के तथाकथित पहले खाड़ी युद्ध से लेकर, अमेरिका ने 1996 में और फिर 1998 में जब चाहे तब इराकी सैन्य सुविधाओं पर तथा सद्दाम के आवासों पर मनमानी बमबारी की। व्यापक तबाही मचाई। इराक की संप्रभुता पर हुए इन सभी हमलों को राष्ट्र संघ की स्वीकृति थी। अब इस ताजातरीन युद्ध में भी जब अमेरिका भयानक बमबारी करते हुए हजारों लोगों का कत्लेआम कर रहा था और व्यापक तबाही मचा रहा था, तब भी राष्ट्र संघ का चुप्पी साध लेना एक घोर अपराध था।

इससे भी बदतर यह था कि राष्ट्र संघ की सहमति से अमेरिका ने इराक पर कई अमानवीय प्रतिबन्ध लगाए। उसे अपना तेल बेचने के लिए भी राष्ट्र संघ की इजाजत लेना अनिवार्य बनाया। इराक की संप्रभुता की अवहेलना करने वाले राष्ट्र संघ के प्रतिबन्धों के तहत इराक को आवश्यक दवाओं का निर्यात बन्द कर दिया गया। इससे करीबन 15 लाख लोगों की मौत हुई जिनमें आधा मासूम बच्चे थे। इन अमानवीय प्रतिबन्धों के दिल दहलाने वाले दुष्प्रभावों को अमेरिकी शोधकर्ता जॉन म्युल्लर और कारल म्युल्लर के इस निष्कर्ष से समझा जा सकता है कि "सम्भवतः नरसंहार के तमाम हथियारों के बनिस्बत आर्थिक प्रतिबन्धों से ही ज्यादा लोग

मारे गए।”

कुछ लोग नरमी विरोध जताते हुए यह तर्क दे रहे हैं कि इराक को निशस्त्र बनाने का काम राष्ट्र संघ का था, अमेरिका को इस तरह की आक्रामक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन राष्ट्र संघ सबसे पहले अमेरिका को क्यों नहीं निशस्त्र बनाता? ब्रिटेन को क्यों नहीं? नरसंहार के सबसे घातक व सबसे ज्यादा हथियार तो उन्हीं के पास मौजूद हैं। ऐसे लोग एक गलतफहमी फैलाने में कामयाब हो गए कि अगर राष्ट्र संघ की सहमति हो तो किसी भी देश से युद्ध करना जायज है। ये लोग एक कड़वी सच्चाई से अपनी आंख बन्द कर रहे हैं कि राष्ट्र संघ साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों की एक कठपुतली भर है। किसी देश की सम्प्रभुता पर हमला करने का अधिकार राष्ट्र संघ को भी नहीं है।

अन्य साम्राज्यवादियों का 'विरोध'

हमने ऊपर देखा है कि अमेरिका के इस एकतरफा युद्ध का कुछ अन्य साम्राज्यवादी देशों ने विरोध किया। इससे साम्राज्यवादियों के आपसी अन्तरविरोध की एक झलक तो मिल जाती है। लेकिन इन साम्राज्यवादियों के 'विरोध' के पीछे लोकतंत्र का पक्ष लेने या एक देश की सम्प्रभुता को मान्यता देने का कोई नेक इरादा तो नहीं था। इन्होंने राष्ट्र संघ प्रस्ताव का 'विरोध' करने के सिवाए कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया।

असल में फ्रान्स, जर्मनी, रूस जैसे साम्राज्यवादी देश इराक की लूट में अपना हिस्सा चाहते हैं। इन देशों ने सुरक्षा परिषद में अमेरिकी युद्ध को वैधता दिलवाने वाले प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया। लेकिन ज्यों ही युद्ध शुरू हुआ, इन्होंने एक से बढ़कर एक अमेरिका की विजय की कामना की। फ्रान्स के राष्ट्रपति जांक शिराक ने अपने देश की वायु सीमा को इस्तेमाल करने का अनुमोदन अमेरिकी वायुसेना को दिया। जर्मन विदेशमंत्री योशका फिशर ने खुलेआम घोषणा की कि उसकी आकांक्षा है कि सद्दाम हुस्सेन के शासन का जल्दी से पतन हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यही आकांक्षा प्रकट की। इस युद्ध के पहले इराक को निशस्त्र बनाने की साजिश में भी इन सरकारों का हाथ था। इस युद्ध में लूटी गई सम्पदा में एक हिस्सा पाने की आशा से ही इन्होंने युद्ध में अमेरिका का समर्थन किया। युद्ध के पहले इराक के साथ किए गए व्यापार समझौतों को भी अमेरिका से मान्यता देने का आश्वासन मिले, यह भी उनकी तमन्ना थी। युद्ध के पहले राष्ट्र संघ में नैतिकता पर अनर्गल बयानबाजी करने वाले पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने, ज्यों ही संकट शुरू हुआ, अपने देशों की अत्यधिक जनता के विरोध को भी नजरअन्दाज करते हुए जिस तरह से अमेरिका का समर्थन किया, इससे साम्राज्यवाद जनता के सामने नंगा हो गया। यह स्थिति साम्राज्यवाद और विश्व जनता के बीच अन्तरविरोध को और तीखा कर देती है।

युद्ध के असली कारण

इन दुराक्रमणकारियों ने जो कारण युद्ध के बताए हैं, वे वास्तविक नहीं थे बल्कि वास्तविकता पर पर्दा डालने वाले थे। ***युद्ध के असली कारण थे :*** **इराक का तेल; डॉलर तथा यूरो में वर्चस्व की लड़ाई; पश्चिम एशिया को पूरी तरह से अमरिकी प्रभुत्व में लाना; और युद्ध रूपी आक्सिजन से अमेरिका की आर्थिक बदहाली से उबरना।**

इराक विश्व के दो प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक है। इराक के तेल को अपने कब्जे में लाकर अमेरिका न सिर्फ अपने देश के भीतर तेल की आपूर्ति को लेकर निश्चिन्त हो जाता, बल्कि तेल उद्योग में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इजारेदारी तेल को कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का भी मौका प्रदान करती। इस इजारेदारी के जरिए अमेरिका के बड़े पूंजीपति जो अत्यधिक मुनाफा कमाएंगे वह अलग। अमरिका के लिए परेशानी की वजह यह थी कि सद्दाम के रहते इराक के तेल पर उसका काबू नहीं हो सकता। आज से बीस साल पहले बेक्टेल कम्पनी के लिए इराक-जोर्डन पाइप लाइन का ठेका लेने गए रम्सफेल्ड को, जो आज अमेरिका का रक्षामंत्री है, बैरंग वापस लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, वर्तमान में इराक के तेल के बारे में सद्दाम ने कई समझौते रूस व फ्रान्स के साथ किए। कोई आश्चर्य नहीं कि अमेरिकी तेल लॉबी का मुख्य पैरोकार रम्सफेल्ड इराक पर युद्ध के लिए सबसे ज्यादा उतावला था।

पिछले कुछ समय से मुद्रा जगत् की मुख्य घटना डॉलर तथा यूरो के बीच का टकराव है। इस टकराव में यूरो का, जो यूरोपियन यूनियन की मान्य मुद्रा है, पलड़ा भारी था। डॉलर की कीमत में

विश्व जनता का जबर्दस्त विरोध

इस युद्ध के प्रारम्भ से पहले भी और युद्ध के दौरान भी विश्व जनता ने जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन किए थे, वह अपने आप में बेमिसाल था। जिन देशों ने युद्ध का समर्थन किया – जैसे कि स्पेइन, इटली, पुर्तगाल – वहां भी जनता ने शानदार विरोध प्रदर्शन किए। युद्ध के प्रारम्भ के पहले, 15 फरवरी को विश्व भर में ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किए गए थे। एक अनुमान है कि दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के 600 शहरों महानगरों में कुल मिलाकर लगभग डेढ़ करोड़ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका की युद्ध की तैयारियों के खिलाफ आवाज उठाई। रोम में 25 लाख, माड्रिड में 15 लाख, बार्सिलोना में 15 लाख, लन्दन में 15 लाख, न्यूयार्क में 7 लाख 50 हजार, कोलकाता में 3 लाख, एथेन्स में 2 लाख – प्रदर्शनकारियों की संख्या के ये कुछ आंकड़े यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि इराक युद्ध के खिलाफ जनाक्रोश विश्व का सबसे तीखा और व्यापक युद्ध विरोधी आन्दोलन है। जनता के इस व्यापक विरोध को नजरअन्दाज करके अमेरिका ने खुद को विश्व जनता का नम्बर एक दुश्मन साबित किया। जनता ने उसके मानवता-विरोधी चरित्र को अच्छी तरह समझ लिया। ❑

गिरावट आ रही थी तथा यूरो मजबूत हो रहा था। डॉलर का कमजोर पड़ना अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय साख एवं अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही खतरनाक था। सद्दाम पर अमरिका के गुस्से का यह भी एक कारण था कि इस स्थिति को पैदा करने में उसकी भूमिका थी। उसने इराक के विदेशी जमा को डॉलर की जगह यूरो में करके तथा इराकी तेल की कीमत यूरो में लेने का फैसला करके अमेरिका को गहरी चोट पहुंचाई थी। इराक की तर्ज पर कुछ अन्य तेल निर्यातक देशों के यूरो को इस्तेमाल करने की सम्भावना से अमेरिकी लुटेरे घबराए हुए थे। नई अमेरिकी सदी का सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा था।

पश्चिम एरिया को हर कीमत पर अपने पूर्ण राजनीतिक एवं सैनिक नियन्त्रण में लेना है, यह अमेरिका की एकध्रुवीय नई विश्व व्यवस्था का आधार है। इसी सिद्धान्त के चलते इराक पर हमला हुआ तथा युद्ध पूरी तरह से खत्म होने के पहले ही सिरिया को धमकाने का काम शुरू हो गया। पश्चिम एशिया में अमेरिका का चेला इस्राएल पिछले छह दशकों से अरब जनता पर हमले करता आ रहा है। उसने अमेरिका की मदद से फिलिस्तीन, सिरिया, जोर्डान और लेबनान पर कई बार हमले किए और उनके भूभागों को हड़प लिया। फिलिस्तीनी लोग इस्राएल के क्रूर अत्याचारों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। सद्दाम फिलिस्तीनियों के संघर्ष का समर्थन करता है, यह भी अमरिकी हितों के लिए एक खतरा था क्योंकि अमेरिका इस्राएल के सहारे पूरे पश्चिम एशिया को अपने कब्जे में रखना चाहता है। और इसलिए भी सद्दाम अमेरिका का दुश्मन बन गया।

सबसे महत्वपूर्व बात यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था घोर संकट में फंस चुकी है। उसे खासकर यूरोपीय यूनियन और जापान से कड़ी टक्कर मिल रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका की स्थाई युद्ध अर्थव्यवस्था एक अनिवार्य परिणाम था। जिस दिन हथियारों के कारखाने बन्द हो जाएंगे उसी दिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। उसका सैन्य खर्च समूची दुनिया के खर्च में लगभग आधा है। यदि यह खर्च कम किया जाए तो बेरोजगारी की दर अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाएगी जिससे तेज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए, सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादियों को कुछ दुश्मन ढूंढ़ने पड़े ताकि उसकी युद्ध की मशीन चलती रह सके। इसलिए वह अपने सैन्य खर्चों को लगातार बढ़ा रहा है। संकट में गले तक फंसी हुई उसकी अर्थव्यवस्था के लिए 11 सितम्बर जैसे वरदान साबित हुआ। इस्लामिक आतंकवाद को बड़े खतरे के रूप में चित्रित करना शुरू किया और सैन्य खर्च की व्यापक योजनाएं तैयार कीं। विश्व में होने वाले 800 अरब डॉलर के हथियार व्यापार का आधा हिस्सा अमेरिकी कम्पनियों का है। अमेरिकी शासक वर्गों के लिए युद्ध और हथियार उद्योग जीवन-रेखा बन गए।

युद्ध के बाद 'पुनर्निर्माण', पर किसका?

युद्ध के परिणामस्वरूप होने वाले महाविनाश के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण के नाम पर अमेरिका की कम्पनियां इराक का आर्थिक दोहन कर अत्यधिक मुनाफा कमाने और अमेरिका की बदहाल अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए जो योजनाएं लेकर आ रही हैं, वे युद्ध के निहित स्वार्थी चरित्र और असली कारण को उजागर कर देती हैं। अमेरिका की एक प्रसिद्ध कम्पनी हैलीबर्टन की सब्सिडियरी शाखा को तेल कूपों की मरम्मत का 50 करोड़ डॉलर का, जो बढ़कर 750 करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है, ठेका मिल चुका है। इस कम्पनी के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी का नाम जुड़ा है। इस तथाकथित दूसरे खाड़ी युद्ध में अमेरिका की 'विजय' के बाद जिस जे गारनर को इराकी प्रशासन की बागड़ोर सौंपी गई वह एक भूतपूर्व सैन्य जनरल ही नहीं, बल्कि मिसाइल बनाने वाली एक कम्पनी – एल-3 कम्युनिकेशन्स – का अधिकारी भी था। बताया जाता है इराक पर दागी गई कुछ मिसाइलें इसी गारनर की कम्पनी की तकनीक से बनाई गई थीं। पुनर्निर्माण कार्य के 90 करोड़ डॉलर के ठेके के लिए, जो अरबों डॉलर का काम हो सकता है, वे पांच कम्पनियां दौड़ में हैं जिन्होंने बुश के चुनाव अभियान के लिए लाखों डॉलर दिए थे। इराक के कृषि क्षेत्र पर नियंत्रण जमाने के लिए क्राफ्ट तथा अन्य अमेरिकी कम्पनियों ने तैयारी शुरू कर दी है। शस्त्र उद्योग के क्षेत्र में इस युद्ध में किए गए प्रदर्शन के आधार पर लोकहेड, बोइंग तथा जनरल डाइनेमिक जैसी कम्पनियां टॉमहॉक तथा एजीएम 154 मिसाइल व अन्य हथियार बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाने की सोच रही हैं।

इससे साफ मालूम हो जाता है कि अमेरिका के इस युद्ध के फैसले के पीछे कौन सी ताकतें मौजूद थीं। और यह भी कि 'पुनर्निर्माण' के नाम पर इराक में जो कोशिश चल रही है, दरअसल वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने की कवायद ही है।

इराकी जनता का बहादुराना मुकाबला

एक लगभग निहत्थे देश ने महाशक्ति को तीन सप्ताह तक कैसे टक्कर दी? चौबीसों घण्टों की बेरोकटोक बमबारी के बाद बगदाद की तस्वीर क्या हो गई होगी? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। मानव इतिहास में इस बेहद असमान युद्ध में इराकी जनता ने बुलन्द हौसलों का जो प्रदर्शन किया, वह विश्व जनता के लिए एक आदर्श है। अमेरिकी युद्धोन्मादियों ने सोचा था कि वे इराक को चंद घण्टों में नहीं तो चंद दिनों में कब्जा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सप्ताह के बाद वे किसी एक शहर पर भी कब्जा नहीं कर पाए। उन्हें लगभग एक लाख अतिरिक्त फौजों को बुलाना पड़ा। उन्होंने सैकड़ों निहत्थे नागरिकों को मार डाला ताकि उन्हें विरोध का सामना न करना पड़े। जो दिखाई दिया उस पर ग्रेनेड दागी या गोली चलाई। रिहायशी इलाकों पर कार्पेट बमबारी की।

इराकी जनता को पानी, बिजली, ईंधन, स्वास्थ्य सुविधा आदि से वंचित करके उन्हें अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना अमेरिकी-ब्रितानी दरिंदों की रणनीति रही। लेकिन इराकी जनता ने धैर्य का परिचय दिया, घुटने नहीं टेके। वे शुरू से ही लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। अब जबकि युद्ध की औपचारिक समाप्ति हो गई, इराकी जनता ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाकर अमेरिकी आक्रमणकारियों के नाकों दम करके रख दिया। आए दिन कहीं न कहीं से अमेरिकी सैनिकों पर और उनके काफिलों पर हमलों की खबरें आ रही हैं। अनेक अमेरिकी सैनिक कुत्तों की तरह मर रहे हैं। नागरिक सुविधाओं के लेकर जनता हर दिन आक्रमणकारी सैनिक शासकों के खिलाफ विरोध

प्रदर्शन कर रही है।

अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने यह सपना देखा था और इसे सच बनाने की साजिश भी की कि इराक में जब वे हमला करेंगे तब शिया मुसलमान सद्दाम शासन के खिलाफ बगावत कर देंगे और उनका पल्ला थाम लेंगे। अमेरिकी जनता को भी उन्होंने ऐसा ही आश्वस्त किया हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इराक में शिया मुसलमानों की आबादी 60-65 प्रतिशत है और सद्दाम ने उनका उत्पीड़न भी कर रखा था, लेकिन शिया लोगों ने अमेरिकी आक्रमणकारियों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ दृढ़तापूर्वक विरोध का रास्ता अपनाया।

साम्राज्यवादियों के टुकड़ों पर पलने वाले मीडिया की भूमिका

इस युद्ध में साम्राज्यवाद के पक्ष में मीडिया ने जिस तरह की भूमिका निभाई वह भी 'ऐतिहासिक' ही है। हालांकि फासीवादियों के लिए गोबेल्स की तरह का दुष्प्रचार कोई नई बात नहीं है, फिर भी इस युद्ध में जिस शर्मनाक हद तक इसका दुरुपयोग किया गया वह हैरान कर देने वाला है। अपनी निष्पक्षता का ढिंढ़ोरा पीटने वाले बीबीसी ने वास्तव में 'बुश-ब्लेइर कॉर्पोरेशन' की तरह काम किया। सीएनएन, एनबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, आदि सभी माध्यमों ने असत्यों, गढ़े हुए सत्यों या अर्ध सत्यों का खुला प्रचार किया। उदाहरण देखिए, जबकि न्यूयार्क में राष्ट्र संघ के मुख्यालय के पास 7½ लाख लोगों का प्रदर्शन हो रहा था, तब वीओए ने युद्ध के समर्थन में 50 लोगों द्वारा किए गए प्रदर्शन को बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित किया था। सभी प्रचार माध्यमों ने झूठों का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि झूठों को बार-बार दोहराकर जनमत को प्रभावित करने में भी सफलता प्राप्त की। खासकर 11 सितम्बर की घटनाओं के बाद अमेरिकी जनता में यह प्रचारित किया गया कि सद्दाम से अमेरिका को खतरा है क्योंकि अल क़ायदा के साथ उसके सम्बन्ध हैं। सितम्बर 2001 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार सिर्फ 3 प्रतिशत अमेरिकी ही 11/9 के हमलों के लिए सद्दाम को दोषी मानते थे, लेकिन मीडिया के दुष्प्रचार की आंधी से एक साल बाद ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि 50 प्रतिशत से ज्यादा अमेरिकी सद्दाम को दोषी मानने लग गए। यह एक उदाहरण ही है।

मीडिया पर, जिसे लोकतंत्र के आधार-स्तम्भों में एक कहा जाता है, साम्राज्यवादियों का एकाधिकार कायम है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में क्लीयर चैनल वर्ल्ड वाइड इंकार्पोरेटेड एक कम्पनी है जिसके सबसे ज्यादा रेडियो स्टेशन हैं और 1200 से ज्यादा चैनल हैं। बाजार में इस कम्पनी का हिस्सा 10 प्रतिशत है। इस कम्पनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ने बुश के चुनाव प्रचार अभियान के लिए लाखों डॉलर चंदा दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब इराक पर जबरन युद्ध थोपने के बुश के फैसले के खिलाफ लाखों अमेरिकी प्रदर्शन कर रहे थे, क्लीयर चैनल ने 'अमेरिका के समर्थन में कई देशभक्तिपूर्ण रैलियां' आयोजित करवाईं। यह एक मकड़जाल है जिसमें हथियार व्यापारियों, मीडिया सम्राटों और राजनेताओं का अजीब सा घालमेल है।

भारतीय शासक वर्गों का दिवालियापन

इराक पर अमेरिकी दुराक्रमण के खिलाफ भारत के शासक वर्गों ने जो रवैया अपनाया उससे उनका दलाल चरित्र फिर एक बार नंगा हो गया है। युद्ध के आखिर तक उन्होंने अपना कोई निश्चित रवैया स्पष्ट होने नहीं दिया। यहां तक कि युद्ध के दौरान अमेरिकी विमानों को ईंधन भर लेने की सुविधा मुहैया करवाने की सम्भावना को भी रद्द नहीं किया। लोकसभा में आमेरिकी आक्रमण पर निंदा प्रस्ताव के दौरान, भाजपा ने काफी नानुकर करके अपने अमेरिका-अनुकूल चरित्र को उजागर किया। वाजपेयी सरकार इराक में पुलिस का काम लेने के लिए भी बेचैन है ताकि अपने अमेरिकी आकाओं का हाथ बंटा सके। इनकी आशा है कि अमेरिका इस युद्ध से प्राप्त लूट के ठेकों में एक छोटा हिस्सा भी तो भारत के दलाल पूंजीपतियों को देगा। लेकिन इस तरह वे भारत की जनता के सामने बेनकाब हो गए। इराक में भारतीय सेना द्वारा पुलिसिया काम की सम्भावना को लेकर जनता में जबर्दस्त विरोध उठ खड़ा हो रहा है।

साम्राज्यवाद के खिलाफ जुझारू जन-संघर्ष ही एक मात्र रास्ता

अमेरिकी-ब्रितानी साम्राज्यवादियों के इराक पर दुराक्रमण के खिलाफ विश्व जनता की एकजुटता काबिले तारीफ थी। कई जन संगठनों ने अमेरिकी-ब्रितानी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान भी किया। कई देशों में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर लोगों ने हमले करके अपना विरोध व्यक्त किया। इराक से अमेरिकी फौजों को वापिस जाने की मांग करते हुए विश्व जनता को अपनी आवाज बुलन्द करनी चाहिए। आक्रमाणकारी सेनाओं के खिलाफ जूझ रहे इराकी लोगों का तहेदिल से समर्थन करना चाहिए।

इस भूगोल को साम्राज्यवादी युद्धों से मुक्त करना है तो वह सिर्फ और सिर्फ जनता ही कर सकती है। साम्राज्यवाद को खत्म करके समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना ही एक मात्र विकल्प है जिससे युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर देने का रास्ता बन सकता है। आज अमेरिकी साम्राज्यवाद दुनिया में अलग-थलग पड़ चुका है, जो एक अनुकूल परिणाम है। एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उसका सपना भी दिवास्वप्न ही साबित हो रहा है। इस युद्ध में यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों, रूस और चीन से उसे विरोध का सामना करना पड़ा। उनके साथ उसका अन्तरविरोध और भी बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि आखिर साम्राज्यवाद एक ऐसा भेड़िया है जिसकी भूख मिटाए नहीं मिटती। वे विश्व पर अमेरिका के एकाधिकार को चुप्पी साधकर मान लेने को तैयार नहीं हैं। साम्राज्यवाद के रोज-रोज गहराते संकट से उनके बीच अन्तरविरोध और ज्यादा तीखे बनेंगे। इससे और युद्ध हो सकते हैं। युद्धों का मतलब जनता की सम्पूर्ण तबाही। निश्चय ही इससे सभी देशों में आर्थिक व राजनीतिक उथल-पुथल मचेगी।

हम अपनी सारी ताकतों को गोलबन्द करेंगे और मौजूदा अनुकूल स्थिति का फायदा उठाते हुए अमेरिकी साम्राज्यवाद को पूरी तरह से अलग-थलग कर देंगे। युद्ध और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक जुझारू आन्दोलन खड़ा करेंगे। ❑

28 जुलाई के मौके पर शहीदों की कुरबानी याद करें !

28 जुलाई ... भारत में शहीद दिवस। यह वही दिन था जिस दिन भारत के क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन के निर्माता व मार्गदर्शक कॉमरेड चारु मजुमदार को कोलकाता में 31 साल पहले पुलिस की हिरासत में क्रूरतापूर्वक मार डाला गया था। इस दिन हम अपने तमाम प्यारे साथियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए क्रूर उत्पीड़कों के खिलाफ लड़ते हुए निस्वार्थता से अपने प्राणों को न्यौछावर किया। कैसी आजादी... अन्याय से आजादी, सामाजिक भेदभाव से आजादी, साम्राज्यवादी आधिपत्य से आजादी और निर्दयतापूर्ण शोषण व उत्पीड़न से आजादी!

इस साल, 2003 में, हम इस दिन खासतौर पर उन चार वरिष्ठ कॉमरेडों को याद करेंगे जिन्होंने अपने खून से आन्ध्रप्रदेश के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में एक नया अध्याय रच दिया। **उत्तरी तेलंगाणा के स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य कॉमरेड रामकृष्ण (सुदर्शन रेड्डी) और कॉमरेड सुधाकर (अनपुरम कोमुरय्या), हैदराबाद नगर कमेटी सचिव कॉमरेड रमणा रेड्डी और आदिलाबाद जिला कमेटी सचिव कॉमरेड ललिता (साधना)** — ये चारों कॉमरेड दो माह के अन्तराल में ही मारे गए जिससे भारत की क्रान्ति को, खासकर तेलंगाणा के आन्दोलन को जबर्दस्त नुकसान हुआ। वे इस समाज में जन्मे ऐसे महत्वपूर्ण शख्स थे जिन्होंने न्याय व समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ त्यागना पसन्द किया। जंगलों और खेतों में गुजरने वाली छापामार जिन्दगी में उत्पन्न सभी कठिनाइयों का उन्होंने धैर्य के साथ और मुस्कराते हुए सामना किया। वे अपने 15-20 सालों की क्रान्तिकारी जिन्दगी में अपने साथियों से सदैव प्रेम व स्नेह के साथ पेश आते रहे और गरीब व शोषित जनता में वे काफी लोकप्रिय थे। वे अनुभवी और वर्ग संघर्ष में गहरा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। जंगे मैदान में उन्होंने बहादुरी, सूझबूझ व कुरबानी की कई मिसालें कायम की थीं। उनके दिल में शोषकों और उत्पीड़कों के खिलाफ वर्ग-नफरत आग की तरह सुलगती रहती थी। यही वजह है कि दुश्मन इनका सफाया करने के लिए हाथ धोकर पीछे लगा हुआ था। इनकी शहादत भारत की नव जनवादी क्रान्ति के लिए एक नुकसान जरूर है, इसके साथ-साथ यह सैकड़ों-हजारों लोगों को प्रेरित भी करती है।

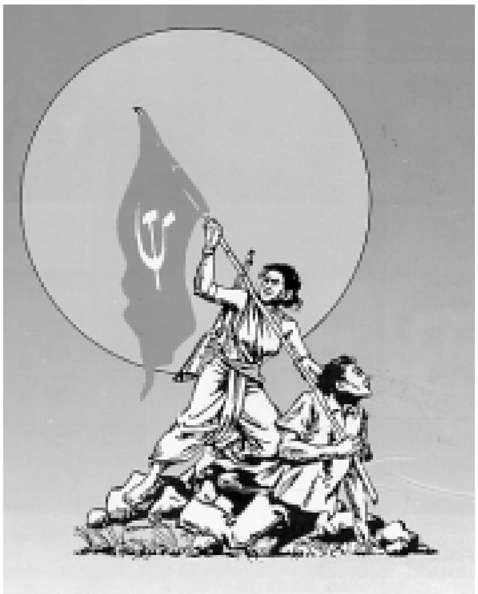

दण्डकारण्य में पिछले वर्ष के शहीद-सप्ताह से अब तक पीजीए के दो युवा जानबाज़ कमाण्डरों की शहादत हुई। प्लटून-2 के सेक्शन कमाण्डर कॉमरेड सन्नू और प्लटून-4 के सेक्शन डिप्यूटी कमाण्डर कॉमरेड भास्कर – इन दोनों कमाण्डरों ने दुश्मन के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ते हुए जंगे मैदान में शहीद हुए थे। इनके अलावा कई जन संगठन कार्यकर्ताओं और अंशकालिक पार्टी सदस्यों की मृत्यु बीमारी व अन्य कारणों से हुई। इस तरह, इस एक साल में पूरे देश में एमसीसीआइ और भाकपा(मा-ले) [पीपुल्सवार] के कोई 300 अन्य क्रान्तिकारियों ने अपनी जानें कुरबान कर दीं। इनमें अधिकतर लोग अपनी युवावस्था में ही थे। इनमें महिला कॉमरेडों की संख्या भी कुछ ज्यादा ही है। इन सभी को हम विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि पेश करते हैं।

हम इस मौके पर उन सैकड़ों-हजारों योद्धाओं को भी याद करेंगे जिन्होंने अपनी राष्ट्रीयता की मुक्ति के लिए क्रूर राजसत्ता के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें न्यौछावर कीं। खासतौर पर कश्मीर व पूर्वोत्तर में शासक वर्गों द्वारा जारी बर्बरतापूर्ण दमन का मुकाबला करते हुए कई योद्धाओं ने संघर्ष का परचम ऊंचे उठाए रखा है। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब कहीं न कहीं गोलीबारी नहीं होती या लुटेरे सैन्य बलों द्वारा हत्या, बलात्कार, लूटपाट, यातना, लापता का कोई न कोई मामला सामने नहीं आता। हालांकि इनमें अपने अन्तिम लक्ष्य के सम्बन्ध में स्पष्टता का अभाव है, फिर भी इनकी आकांक्षा आजादी पाने की थी और ये भारत के उत्पीड़क शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे।

इस मौके पर हम उन हजारों मुसलमानों और दलितों की मौत पर भी शोक व्यक्त करते हैं जिन्होंने हिन्दू फासीवादियों के हमलों में अपने प्राण गंवाए। गुजरात के दंगों के बाद गोधरा से 120 मुसलमानों को पोटा के तहत गिरफ्तार किया गया। लेकिन हजारों मुसलमानों को मारने वाले, जिन्दा जलाने वाले, सामूहिक बलात्कार करने वाले, लूटपाट मचाने वाले हजारों अपराधियों को खुला घूमने की छूट दी गई है। भाजपा व आरएसएस द्वारा प्रायोजित इस भयानक नरसंहार को अंजाम देने वालों को कोई सजा नहीं मिली है। यहां तक कि समूचे विपक्ष ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। राज्य यंत्र के न्यायपालिका समेत सभी विभाग भी चुप हैं।

इस दिन हम उन तमाम योद्धाओं को भी याद करेंगे जिन्होंने नेपाल, पेरू, फिलिप्पीन्स, तुर्की समेत कई अन्य देशों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद का पताका ऊंचे उठाकर प्रतिक्रियावाद के खिलाफ लड़ते हुए बलिदान दिए। साम्राज्यवाद, खासतौर पर अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए अफगानिस्तान, इराक, आदि देशों में मारे गए लोगों की मौत का भी हम शोक मनाएंगे। इस साल इराक पर अमेरिका के आक्रमण के दौरान मारे गए लोगों में 90 प्रतिशत से ज्यादा मासूम ही थे। कायर साम्राज्यवादियों की *(शेष पृष्ठ 10 पर....)*

कॉमरेड्स ललिता, स्वर्णा और कमला की शहादत का बदला लो !
शहीदों के अरमानों को पूरा करने का संकल्प लो !!

14 मई 2003 के दिन उत्तर तेलंगाणा में एक और जन नेता की शहादत हुई – कॉमरेड एल्लंकि अरुणा जो पार्टी की आदिलाबाद जिला कमेटी की सचिव थीं। कॉमरेड अरुणा उत्तर तेलंगाणा में ललिता के नाम से लोकप्रिय थीं, जबकि दण्डकारण्य के आदिवासियों में साधना के नाम से लोकप्रिय थीं। स्वर्णा और कमला नामक अन्य दो कॉमरेडों के साथ कॉमरेड ललिता की मृत्यु आदिलाबाद जिले के बेज्जूर मण्डल, अगरुगूडेम जंगल में हत्यारे ग्रे-हाउण्ड्स बलों के साथ हुई एक जबर्दस्त मुठभेड़ में हुई। इन बहादुर साथिनों ने हमलावर पुलिस को कड़ी टक्कर देकर अपने साथियों को सुरक्षित बच निकलने का रास्ता बनाया।

कॉ. ललिता का जन्म संघर्ष का गढ़ कहलाने वाले करीमनगर जिले के बंडालिंगापुर गांव में कोई 40 बरस पहले हुआ था। उनका परिवार मध्यम वर्ग का था। उनके पिताजी गांव में पटवारी का काम करते थे। उनका गांव उस जमाने में सामंतवाद का गढ़ हुआ करता था। इस तरह उनका बचपन सामंती रीति-रिवाजों के बीच ही गुजरा था। बचपन में ही उनकी शादी करवा दी गई थी। लेकिन अनैतिक व पुरुष अहंवादी पति ने ललिता को प्रताड़ित किया था। बाद में उन्होंने अपने पति से तलाक ले ली और घर पर रहने लगीं। इस बीच उन्हें कोढ़ की बीमारी का शिकार होना पड़ा था। यह उनकी निजी जिन्दगी में बेहद कठिन व पीड़ादायक दौर था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इलाज करवा लिया। बाद में पास का एक कस्बा कोरुट्ला में इंटरमीडियट में दाखिला ली। तब वह रैडिकल छात्र संगठन (आरएसयू) के सम्पर्क में आ गईं। यहीं से उनकी जिन्दगी ने एक जबर्दस्त मोड़ ले लिया। बहुत जल्द ही उन्होंने क्रान्तिकारी राजनीति को आत्मसात किया और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप काम करने लग गईं। आदिलाबाद जिले के निर्मल शहर में उन्होंने अध्यापन के प्रशिक्षण कोर्स में दाखिला ली। वहां भी उन्होंने अपनी सक्रियता जारी रखी।

कॉमरेड एल्लंकि अरुणा (ललिता/साधना)

1983 में उन्होंने पार्टी के एक संगठक (कॉमरेड आनन्द, जो अब पार्टी का केन्द्रीय कमेटी सदस्य है) को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला लिया। उन्होंने तीन साल तक शिक्षिका के रूप में नौकरी की। आदिलाबाद के उन गांवों में, जहां उन्होंने पढ़ाया, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों में वह काफी लोकप्रिय हुई थीं। शिक्षिका के रूप में काम करते हुए उनका आत्मविश्वास बढ़ गया कि वह पेशेवर क्रान्तिकारी के रूप में काम कर सकती हैं। 1988 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और क्रान्ति को अपना जीवन समर्पित किया।

सबसे पहले उन्हें पार्टी ने महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले में काम करने के लिए भेजा जो दण्डकारण्य आन्दोलन का हिस्सा है। उन्होंने कोरची तहसील में आदिवासी महिलाओं के बीच काम शुरू किया, साधना के नाम से। कोरची, टिप्रागढ़, बोरेगांव इलाकों में उन्होंने साधना बनकर 'क्रान्तिकारी आदिवासी महिला संगठन' (केएएमएस) के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। पुलिसिया दमन की परवाह न करते हुए उन्होंने ग्रामीण महिलाओं में इस तरह घुलमिलकर काम किया जैसे पानी में मछली घुलमिल जाती। उन्होंने आदिवासियों की भाषा – गोण्डी – सीखी और उनकी संस्कृति तथा रीति-रिवाजों को समझने की कोशिश की। उनकी खासियत यह थी कि अपनी शिक्षिका की पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने बहुत जल्द ही खुद को आदिवासियों के बीच काम करने लायक बनाया। उस समय महिलाओं के बीच काम करने के लिए पार्टी ने विशेष टीमें बनाई थीं जो निहत्थे ही सादे कपड़ों में संगठन का काम किया करती थीं। लेकिन सरकारी दमन बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद इन टीमों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। बाद में उन्हें नियमित दस्ते में ले लिया गया। वह अपने खाली समय में दस्ते के अनपढ़ सदस्यों को पढ़ाया करती थीं। उन्होंने अपने साथियों का स्नेह जीत लिया। जनता के प्रति अपनी अथाह प्रतिबद्धता के बल पर उन्होंने न सिर्फ अपने साथियों का विश्वास जीत लिया, बल्कि खुद पर भी विश्वास बढ़ाया। 1993 तक वह गड़चिरोली डिवीजन में काम करती रहीं।

पार्टी ने उन्हें 1993 में आदिलाबाद जिला भेजा। उन्होंने खानापुर छापामार दस्ते में काम की जिम्मेदारी ली और उसकी कमाण्डर बनीं। उनके नेतृत्व में उस इलाके के किसानों को बड़े पैमाने पर गोलबन्द किया गया। बाद में जिला कमेटी की सदस्या बनकर वह चेन्नूर इलाके की जिम्मेदारी ली। वहां पर वह बहुत जल्दी ही उत्पीड़ित जनता की चहेती बन गईं। भूमिपतियों, कुख्यात लुटेरों और पुलिस बलों के लिए वह आतंक का पर्याय बन गईं। उन्होंने खासतौर पर 1998 में कॉमरेड ललिता का सफाया करने के लिए कई प्रकार की साजिशें रचीं। लेकिन कॉमरेड ललिता के सक्षम नेतृत्व में पार्टी उस इलाके में मजबूत बन गई। जनाधार बढ़ गया। इससे उनकी सारी साजिशें विफल हो गईं। भीषण दमन के दौरान उन्होंने दस्ता सदस्यों और जन समुदायों का हौसला बढ़ाया। जब-जब पुलिस के साथ आमना-सामना हुआ, उन्होंने हर बार बहादुराना मुकाबला किया। उनका सफाया करने की पुलिस की सारी कोशिशें पिट गईं। कई मुठभेड़ों में से वह सकुशल बच निकलीं।

2001 के अन्त में उन्होंने जिला कमेटी सचिव की जिम्मेदारी ली।

उत्तर तेलंगाणा के अधिवेशन ने कॉमरेड ललिता को पार्टी की ऐतिहासिक 9वीं कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया। उन्होंने अपनी अस्वस्थता के बावजूद कांग्रेस में सक्रिय भाग लिया। कॉमरेड ललिता ने अपनी आखिरी सांस तक एक बेजोड़ योद्धा के रूप में लड़ाई जारी रखी। पार्टी के सदस्यों और आम जनता के लिए वह एक आदर्श हैं, एक प्रेरणा-स्रोत हैं। आदिलाबाद जिले में पार्टी नेतृत्व को हुए कई नुकसानों के बावजूद वह अपने आखिरी दम तक जनता को सघर्ष में उतारती ही रहीं। बेहद मुश्किल व कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने दस्ता सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ाया।

एक दबी-कुचली महिला एक बेजोड़ यौद्धा कैसे बन गई? बच्चों को पढ़ाने वाली एक साधारण शिक्षिका एक सैन्य विशेषज्ञ कैसे बन गई? सामंती रीति-रिवाजों के बीच पली-बढ़ी एक आम लड़की कैसे हजारों जनता की चहेती नेता बन गई? इन सवालों का जवाब भी इन्हीं में छिपा हुआ है। कॉमरेड ललिता आज इसका एक मिसाल बनकर हमारे सामने हैं। एक पद्मा, एक ललिता.... इनका विकासक्रम उन लोगों के लिए एक अबूझ पहेली जैसा ही है जो वर्ग संघर्ष के द्वन्द्वात्मक नियम नहीं जानते। वर्ग संघर्ष ने ही इन्हें समाज की सबसे निचली परत से उठाकर जनता की नायिकाओं में बदल दिया। उन्होंने इतिहास द्वारा सौम्पी गई जिम्मेदारी अपनी जिन्दगी के आखिरी पल तक बखूबी निभाई।

कॉमरेड ललिता को मारकर दुश्मन ने जश्न मनाया। एक ऐसी सैन्य विशेषज्ञ को मारने का दावा किया जो उड़ती हवाई जहाज को भी मार सकती थी। भले ही वह खुशी से पागल होकर कुछ ज्यादा ही बोल गया हो, लेकिन यह सच है कि कॉमरेड ललिता वाकई एक जानबाज़ लड़ाकू थीं। उन्होंने दुश्मन के अनेक हमलों का बड़े धैर्य व बहादुरी के साथ, बिना किसी हड़बड़ाहट के मुकाबला किया। कुछेक बार तो वह अकेली थीं, या उनके साथ इक्के-दुक्के साथी ही थे। फिर भी उन्होंने सूझबूझ के साथ दुश्मन से लोहा लिया। कई बार कैम्पों में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की पुरी कमान अपने कंधों पर ली। दुश्मन का जब भी हमला होता, प्रतिरोध की पहली कतार में कॉमरेड ललिता जरूर रहतीं। 1999 में दुश्मन ने पार्टी के तीन केन्द्रीय नेताओं – कॉमरेड श्याम, कॉमरेड महेश और कॉमरेड मुरली – की हत्या की थी। तब समूचा आन्ध्रप्रदेश शोक में डूबा हुआ था। जगह-जगह पर प्रतिशोध के शोले भड़क उठे थे जो महीनों तक जारी थे। इस सिलसिले में आदिलाबाद के छापामारों ने बेल्लमपल्लि कस्बे में डीएसपी के दफ्तर पर एक जबर्दस्त हमला कर दिया। इस हमले का नेतृत्व कॉमरेड ललिता ने उस टुकड़ी की उप-कमाण्डर के तौर पर किया। दुश्मन से दो एसएलआर रायफलें भी छीन लीं। आज कॉमरेड ललिता की मृत्यु से पीजीए बलों ने एक जानदार कमाण्डर को गंवाया।

कॉमरेड ललिता अपने साथियों के साथ और जनता के साथ किस तरह का बरताव किया करती थीं, यह नहीं बताने पर उनके जीवन का चित्रण अधूरा ही होगा। हालांकि आमतौर पर कम्युनिस्ट मानवीय गुणों से भरे होते हैं, यही वजह है कि वे मानवजाति को उत्पीड़न के बन्धनों से मुक्त कराने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। कॉमरेड ललिता एक उत्तम कम्युनिस्ट थीं। वह अपनी बुद्धिजीवी की पृष्ठभूमि के बावजूद विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए इलाकों में जाकर आदिवासी स्त्री-पुरुषों के साथ जिस तरह एकताबद्ध हुई थीं, उससे हर कम्युनिस्ट को सीखना होगा। वह अपने साथियों का हर दुख-दर्द बांट लिया करती थीं। पार्टी की कतारों में सभी से वह अच्छे सम्बन्ध कायम कर लेती थीं। जब वह किसी साथी में कोई गलती देखतीं, वह जरूर उसकी आलोचना करतीं। स्नेहपूर्वक बरताव और बेबाक आलोचना – उनमें इन दोनों गुणों का सही मिश्रण होता था। जनता से वह बहुत प्यार करती थीं और उस पर उनका अटूट भरोसा था, यह बात उनकी हर गतिविधि में और उनके हर शब्द में साफ तौर पर झलकती थी। आज उनकी शहादत से उत्पीड़ित जनता और क्रान्तिकारी जनता को एक विनम्र कम्युनिस्ट की कमी जरूर खलती रहेगी।

उत्पीड़ित महिलाओं के प्रति उनका लगाव भी उल्लेखनीय रहा। उन्होंने ऐसी कठिनाइयों का बारीकी से अध्ययन किया जिनसे महिलाओं के क्रान्तिकारी आन्दोलन में भागीदारी लेने की राह में रुकावटें आ रही हैं। उन्होंने पार्टी में महिलाओं को आन्दोलन में लाने और उन्हें विकसित करने के काम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। वह पहले गड़चिरोली जिले में और बाद में आदिलाबाद जिले में भी महिलाओं को गोलबन्द करने के लिए तथा संगठन में लाने के लिए घर-घर घूमती थीं। उन्होंने पार्टी में तरह-तरह के पितृसत्तात्मक रुझानों के खिलाफ अथक संघर्ष किया। पार्टी में ही नहीं, पूरे समाज में भी पितृसत्ता का जड़ों से सफाया करना उनके महत्वपूर्ण लक्ष्यों में एक था।

वाकई कॉमरेड अरुणा (ललिता/साधना) एक 'अरुणा' तारा की तरह क्रान्ति के आसमान में चमकती रहेगी। क्रान्तिकारी योद्धाओं और आन्ध्रप्रदेश के क्रान्तिकारी जन समुदायों के लिए वह हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। खासकर उन महिलाओं को, जो साम्राज्यवादी व सामन्ती शोषण के बन्धनों में जकड़ी हुई हों, कॉमरेड ललिता की जिन्दगी से, संघर्ष से और शहादत से नैतिक शक्ति मिलेगी। कॉमरेड ललिता को और उनके साथ शहीद हुई कॉ. स्वर्णा और कॉ. कमला को भी 'दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी' नम्रता से श्रद्धांजलि पेश करती है। ❑

(.... 8 पृष्ठ का शेष)

शहीदों की कुरबानी याद करें

रणनीति है कि जमीनी लड़ाई करने से पहले अंधाधुंध व विनाशकारी बमबारी करके लोगों का कत्लेआम किया जाए ताकि उसका विरोध करने की सम्भावनाएं खत्म हो सकें।

इस अवसर पर पिछले साल के बहादुर शहीदों को याद करते समय हमें उनकी वीरतापूर्ण कुरबानी और समझौताहीन लड़ाई से जरूर प्रेरणा लेनी है। और साथ ही साथ, उनके संघर्षों के दोनों सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं से जरूर सबक लेना चाहिए। तभी हम अपने क्रूर दुश्मन के खिलाफ सुचारू रूप से लड़ सकेंगे और यह जंग जीतकर हम एक नई विश्व व्यवस्था की नींव डाल सकेंगे। ❑

पर्चा

गड़चिरोली डिवीजन में पैर पसारने वाले गैर-सरकारी संगठन

श्रमिक एलगार की 'समाज सेवा' में सचाई कितनी?

'70 के दशक में एक छोटे से देश वियतनाम की क्रान्तिकारी जनता ने दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा खतरनाक हथियारों से लैस अमेरिकी साम्राज्यवाद को शर्मनाक पराजय का मजा चखाया था। एक छोटे से देश की गरीब जनता ने इस मिथक की धज्जियां उड़ाकर रख दीं – साम्राज्यवाद अपराजेय है। अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए इस मिथक का बने रहना जरूरी था। बस, उसने ऐसी तरकीबों की खोज शुरू कर दी जिससे उसे पराजय का मुंह न देखना पड़े। और इसी खोज का नतीजा ही है ये 'स्वयंसेवी' या 'गैर-सरकारी' संगठन।

इन गैर-सरकारी संगठनों का पहला काम है उन कारणों का पता लगाना जो आम जनता को साम्राज्यवाद-विरोधी और सरकार-विरोधी संघर्ष की राह तक ले जाते हैं। दूसरा, लड़ाकू संगठनों में घुसकर उनका पतन कर देना। तीसरा, जन संघर्ष को व्यवस्था-विरोधी बनने से रोकना। चौथा, हर हालत में पूंजीवादी लोकतंत्र को बनाए रखना। जनता के बीच ऐसा एक वर्ग तैयार करना जो साम्राज्यवादी लूट की नीति को तीसरी दुनिया के देशों में विकास के नाम से पेश करे। क्रान्तिकारी संगठनों के खिलाफ जहर उगलना भी इनका काम है। ये गैर-सरकारी संगठन साम्राज्यवाद के लिए कितने उपयोगी हैं इस एक बात से जाना जा सकता है कि इनके लिए जरूरी कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए मुंबई में "कालेज ऑफ सोशल स्टडीज" नाम से एक महाविद्यालय ही खोल दिया गया है और इस महाविद्यालय का संचालन कर रहा है भारत का बड़ा दलाल पूंजीपति टाटा।

विश्व बैंक, आइएमएफ जैसे साम्राज्यवादियों के वित्तीय संगठन गरीब देशों को कर्ज देते हैं। और साथ में यह शर्त जरूर होती है कि इन पैसों से सुधार कार्यक्रम चलाने में गैर-सरकारी संगठनों को अवश्य ही शामिल करना है। इन गैर-सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं का खर्च उठाने के लिए साम्राज्यवादी देश या साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां या तो सरकार के जरिए पैसे देते हैं या फिर उन्हें सीधे देते हैं। नतीजे में तीसरी दुनिया के देशों में ये गैर-सरकारी संगठन कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं।

इन्हीं कुकुरमुत्तों में से एक है "श्रमिक एलगार"। इसकी संचालिका है पारोमिला गोस्वामी, जिसने जनता की सेवा करने की ट्रेनिंग ली है दलाल पूंजीपति टाटा द्वारा संचालित "कॉलेज ऑफ सोशल स्टडीज" से और जो चली आई है गड़चिरोली जिले के भामरागढ़ इलाके में, जोकि संघर्ष का एक मजबूत गढ़ है।

"श्रमिक एलगार" को यहां पर निरपराध चिन्ना मटामी की पुलिस द्वारा हत्या का मुद्दा मिल गया। फिर क्या था? लगातार अखबारों में बयानबाजी करके वह सुर्खियों में छा गया। पुलिस के खिलाफ मुकदमा ठोंककर, चिन्ना मटामी के परिवार को उसकी जान की कीमत के तौर पर दो लाख रुपए दिलवा दिए। पर इसने हर संभव कोशिश की कि जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ न जाए। सभी गैर-सरकारी संगठनों की तरह इसने भी जनता को संघर्ष से अलग-थलग करना शुरू कर दिया। मशरूम (कुहकु) खेती का ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहा। बॉयो-फर्टिलाइजर "जैविक खाद" की उपयोगिता और प्रयोग के बारे में मर्कानार के आदिवासी किसानों को समझाना शुरू किया। यहां के दूर-दराज के आदिवासी गांवों को मुम्बई के पूंजी बाजार से जोड़ने की साजिश को हमें समझना चाहिए। मुम्बई बाजार में मशरूम बहुत महंगा है। सील बंद डिब्बों में विदेशों के लिए निर्यात भी होता है। सूखे मशरूम की कीमत 700 रू. से लेकर 1000 रूपया प्रति किलो तक है। मशरूम उगाने वाले किसान से 'एलगार' वाले 100-200 रूपए प्रति किलो की कीमत से खरीदकर ले जाते हैं। यह पूरा काम 'एलगार' के स्वयंसेवक करते हैं। टाटा एक दलाल है तो ये स्वयंसेवक दलाल के नीचे दलाल हैं। इस तरह, यह संगठन सरकारी दमन के खिलाफ कुछ दिखावटी कदम उठाकर और विकास की झूठी योजनाओं का सिलसिला शुरू करके जनता में जगह बनाने का प्रयास कर रहा है।

लेकिन इस इलाके में संघर्षशील व क्रान्तिकारी जनता ने 'श्रमिक एलगार' की चालाकियों को अच्छी तरह समझ लिया। 'श्रमिक एलगार' संगठन ने पुलिस द्वारा जारी जनता की मारपीट, गिरफ्तारी, महिलाओं का बलात्कार, हत्या, आदि का सारा दोष भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] को देना शुरू किया। पुलिस को जन-विरोधी व दमनकारी कार्यवाहियां करने के लिए 'श्रमिक एलगार' ने मानों वैधता ही प्रदान कर दी।

पुलिसिया आतंक व जुल्मों के प्रतिरोध में जन छापामार सेना ने पिछले साल अप्रैल में ग्राम बीनागुण्डा के पास पुलिस के एक वाहन को बम से उड़ाया था। लेकिन छापामारों को यह खबर नहीं थी कि उस वाहन में कुछ मजदूर भी थे। बम विस्फोट के समय कुछ मजदूर घायल हुए और एक जन की मौत हुई। इस घटना पर हमने गहरा खेद व्यक्त किया। पहले से हम प्रचार कर रहे थे पुलिस वालों की गाड़ी में आम लोग मत बैठें। हालांकि वे मजदूर भी इस बात से वाकिफ थे और उन्होंने पुलिस वालों के साथ गाड़ी में बैठने से इनकार भी किया था। लेकिन पुलिस ने जबरन उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया ताकि उनका ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह, एक मासूम मजदूर की मौत और कुछ लोगों के घायल होने के लिए पुलिस ही पूरी तरह जिम्मेदार थी। इस इलाके का हर व्यक्ति जानता है कि सचाई यही है। इस पर परदा डालते हुए 'श्रमिक एलगार' वालों ने बीनागुण्डा काण्ड को लेकर हमें बदनाम करना शुरू किया। इससे साफ जाहिर होता है कि वे किसके पक्ष में हैं और किसके खिलाफ काम कर रहे हैं।

'श्रमिक एलगार' एक जन-विरोधी व प्रतिक्रियावादी संगठन है। वह लुटेरी सरकार का ही पक्षधर है। गड़चिरोली की जागरूक व क्रान्तिप्रेमी जनता इस संगठन को जरूर सबक सिखा देगी।

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]
गड़चिरोली डिवीजनल कमेटी

साम्राज्यवाद-शासित आर्थिक सुधारों के अमल में एक और आगे कदम

1990 के दशक से लेकर अब तक सभी आम बजटों की दिशा एक ही रही है। चाहे वह कांग्रेस का मनमोहन सिंह हो, या संयुक्त मोर्चे का चिदम्बरम या फिर राजग सरकार के यशवन्त सिन्हा/जसवन्त सिंह ही क्यों न हो, सभी ने साम्राज्यवादियों और उनके बहुमुखी संस्थानों के इशारों पर ही बजट बनाया है। मोटे तौर पर सरकार की नीतियों का ढांचा डब्ल्यूटीओ, आइएमएफ और विश्व बैंक ने पहले ही बनाया है। सत्ता में कौन-सी पार्टी है यह कोई माने ही नहीं रखता, बल्कि सभी पार्टियां नव-उपनिवेशी नीतियों को पूरी वफादारी के साथ लागू कर रही हैं। वर्ष 2003-04 का बजट भी, बस इसी दास्तान की कड़ी है।

28 फरवरी 2003 को पेश किया गया आम बजट हाल के इतिहास में सबसे लम्बा बजट था। कुल 196 पैरा वाले इस बजट को पढ़ने में वित्तमंत्री जसवन्त सिंह को पूरे 135 मिनट लगे। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कई राज्यों में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2004 में तो आम चुनाव भी होने वाले हैं। इसे ध्यान में रखकर ही राजग सरकार ने इस बजट के जरिए सभी को लुभाने का जी-तोड़ प्रयास किया। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों के प्रति जनता में बढ़ रहे विरोध को कम करने के लिए ही वित्तमंत्री पद से यशवन्त सिन्हा को हटाकर जसवन्त सिंह को लाया। लेकिन इनके नाम में ही नहीं, बल्कि नीति में भी एकरूपता साफ तौर पर देखी जा सकती है, या यूं कहा जा सकता है कि दोनों एक ही थैली के चट्टे-भट्टे हैं।

> ***सचाई यह है पिछले 4 सालों में रसोई गैस के सिलिन्डर की कीमत 85 रुपए से 250 रुपए तक बढ़ गई। पेट्रोल और डीजल के दामों में 200 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। बजट में इनके मूल्यों को बढ़ाने और बाद में इस फैसले को वापिस लेने से क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तो, चीजों के दाम बजट के पहले भी और बजट के बाद भी बाकायदा बढ़ाए जा सकते हैं !***
>
> **- आम बजट पर एक आम आदमी की टिप्पणी**

अपने लोक लुभावने अन्दाज में जसवन्त सिंह ने आश्वासन दिया कि उसका बजट '*गरीब को पेट में दाना और गृहिणी की टुकिया में आना*' देगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलटा।

बजट के तुरन्त बाद, जहां किसानों की असन्तुष्टि उभर कर आई, वहीं लगभग सभी बड़े औद्योगिक मण्डलों, जैसे चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिक्की, एसोचेम, इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, आदि ने बजट की प्रशंसा के पुल बांध दिए। मध्यम वर्ग का एक हिस्सा जहां एक ओर आयकर राहतों से खुश था, वहीं लघु बचत की ब्याज दरों में कटौती से उसका एक बड़ा हिस्सा निराश था। एक बार फिर, पाकिस्तान के साथ तनाव का हवाला देते हुए, रक्षा खर्च में भारी बढ़ोत्तरी की गई है।

आइए देखें, कि यह बजट क्या कहता है। **बजट का अर्थ है सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा।**

आय :

सरकार की आय के मुख्य स्रोत हैं - अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार की आय का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अप्रत्यक्ष करों से आता है। इस बार, चुनावों का ध्यान रखते हुए सरकार ने 'केलकर कमेटी' की सिफारिशों को तो नज़रअन्दाज कर दिया है। केलकर कमेटी ने आय बढ़ाने के लिए आयकर बेस बढ़ाने की बात की थी, परन्तु कई वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दिए गए हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा वेतनकर्मियों, उच्च मध्यम

क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा?

जसवन्त सिंह ने डीजल और यूरिया महंगा किया, पर एयरकन्डीशनर और विदेशी शराब सस्ती। आम बजट ने मोटार कार, एयरकन्डीशनर, ठण्डे पेयजल पर एक्साइज ड्यूटी को 32 प्रतिशत से 24 प्रतिशत कर दिया है, जिससे ये वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। विदेशी शराब पर लगने वाली ड्यूटी को भी घटा दिया गया है। स्कॉच विस्की की एक बोतल के मूल्य में 1200 रुपए की कटौती की गई; कार की कीमत में 10 हजार से 75 हजार रुपए तक कटौती हुई; प्रत्येक एयर कन्डीशनर की कीमत में लगभग 2 हजार रुपए की कटौती की गई। कच्चे हीरे तथा मूल्यवान पत्थरों पर आयात कर हटा दिया गया है, और सोने पर आयात कर काफी कम कर दिया गया है। इससे ये वस्तुएं भी सस्ती हो जाएंगी। सस्ती होने वाली अन्य वस्तुएं हैं - प्रेशर कुकर, बिस्कुट, नकली जरी, छतरी, लकड़ी का सामान आदि।

महंगाई की चपेट में आए हैं - यूरिया व अन्य कृषि आगतें। इस बजट में 50 किलो ग्राम के यूरिया बैग के बिक्री मूल्य में 12 रुपए, डीएपी और एमओपी के बिक्री मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। रसोई गैस सिलिन्डर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई। किरोसिन की कीमत एक रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई। इसके अलावा मिश्रित उर्वरकों का मूल्य बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है। वनस्पति और रिफाइण्ड तेल अचानक तीन रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल व डीजल में भी, एक बार फिर 50 पैसा प्रति लीटर अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रान्सपोर्ट की लागत बढ़ने से सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। बजट के तुरन्त बाद, 15 मार्च को फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर दी गई। काफी विरोध के बाद उर्वरकों की कीमत में वृद्धि को वापिस ले लिया गया। ❑

क्या भारत की अर्थव्यवस्था विकास के रास्ते पर?

सरकार अपने बयानों से लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर है। लेकिन सचाई क्या है, यह समझने के लिए नीचे दिए गए कुछ तथ्यों पर नजर डालें।

अगर कृषि क्षेत्र पर नजर डालें, जिस पर भारत की बहुसंख्यक आबादी निर्भर है, तो साफ देखा जा सकता है कि 1990 के दशक से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। 1947 के बाद यह पहला दशक है जिसमें प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई हो। इतने लम्बे अरसे से चली आ रही गिरावट का कारण केवल 'सूखा' तो नहीं हो सकता। कृषि क्षेत्र की यह स्थिति सरकार के समर्थन मूल्यों की अनुपस्थिति में और गम्भीर हो गई है। जहां एक ओर, करोड़ों का अन्न गोदामों में सड़ रहा है, वहीं क्रय शक्ति के अभाव में भुखमरी से होने वाली मौतों की संख्या आए साल बढ़ती ही जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र ने भी वर्ष 2002-03 में गम्भीर मंदी देखी। औद्योगिक विकास की दर '90 के दशक के मध्य से लगातार गिर रही है। वर्ष 1995-96 में यह विकास दर 13 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2000-01 में घटकर मात्र 5 प्रतिशत रह गई थी और वर्ष 2001-02 में तो स्थिति और खराब हो गई। कारखानों में तालाबन्दी, छंटनी, बढ़ती बेरोजगारी और मिल मजदूरों द्वारा आत्महत्याएं भी आम हो गई हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार लगभग ठहर गया है। जहां तक विदेशी मुद्रा के भण्डार का सवाल है, इसमें निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी हुई है, परन्तु इसका कारण भी निर्यात में बढ़ोत्तरी नहीं है, बल्कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है।

कुल मिलाकर कहा जाए, तो विदेशी मुद्रा के भण्डार, खाद्यान्न के भण्डार और मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के संकेत नहीं है (जैसा कि सरकार द्वारा पेश किया जाता है), बल्कि सच तो यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। ❑

वर्ग के उपभोक्ता और उद्योगपतियों को होगा। वित्तमंत्री ने अपने बजट में आयकर और निगमित कर की दरों में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है, पर इससे वेतनभोगी वर्ग में पैदा होने वाली नाराजगी को कम करने के लिए मानक कटौती में वृद्धि कर दी है। पांच लाख रुपए तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए, मानक कटौती बढ़ाकर वेतन का 40 प्रतिशत या 30 हजार रुपए, जो भी कम हो, करने का प्रस्ताव किया गया है। यदि वेतन 5 लाख रुपए से ऊपर है, तो मानक कटौती 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की गरज से वित्तमंत्री ने उनकी छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) की सुविधा फिर से बहाल करने का भी ऐलान किया है। वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) लेने वाले कर्मचारियों को भी 5 लाख तक की रकम पर राहत देने का फैसला किया गया है। अब शेयरों पर मिलने वाली डिविडेन्ट आय पर कोई कर नहीं रहेगा और शेयर की खरीद-बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन शेयर कीमतों में बदलाव से मिलने वाला फायदा पर भी कर नहीं रहेगा। व्यापार और व्यवसाय कर रहे निजी व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दू परिवारों को, निजी काम के लिए किए गए भुगतान पर कर की कटौती नहीं करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों इत्यादि के लिए घोषित की गई रियायतों को भी आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है।

फिर एक बार, आय जुटाने के लिए कई वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों की दरें बढ़ा दी गई हैं। साधारण सेवा करों की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। और दस नई सेवाओं पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। हां, कुछ वस्तुओं पर से करों की दर घटा भी दी गई है। और कस्टम कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे जहां एक ओर विदेशी शराब सस्ती हो गई है, वहीं वनस्पति और यूरिया महंगा।

आय जुटाने के अन्य उपायों के रूप में, सरकार ने फिर से विनिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस वर्ष विनिवेश का लक्ष्य 13,200 करोड़ रुपए रखा गया है। गौरतलब है कि पहले सरकार केवल घाटे में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विनिवेश (निजी हाथों में बिक्री) की बात करती थी, पर अब यह कह रही है कि बजट के घाटे को पूरा करने के लिए मुनाफाकारी उद्योगों का विनिवेश आवश्यक है। इसी कड़ी में 26 जनवरी 2003 को संसद की एक आपातकाल बैठक में बीपीसीएल और एचपीसीएल के विनिवेएश का फैसला ले लिया गया।

बजट में कुछ चीजों का मूल्य बढ़ाना और जनता के दबाव के चलते उसे वापिस लेना भी शासक वर्गों की चालाकी है। इससे आम आदमी का गुस्सा तुरन्त उतर जाता है। वह बजट के दूरगामी खतरों पर सोचना छोड़कर कुछ चीजों का दाम घटाने से ही संतुष्ट हो जाता है। शासक वर्गों को यही चाहिए, आम लोग बजट में दर्शाने वाले आंकड़ों के मायाजाल को गहराई से न समझने पाएं।

- आम बजट पर एक बुद्धिजीवी की टिप्पणी

व्यय :

जहां तक सरकारी व्यय का सवाल है, पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव तथा किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सशस्त्र सेनाओं को तैयार रखने के लिए अगले वर्ष में उनके खर्च में 9,300 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जो चालू वर्ष के वास्तविक खर्च से लगभग 17 प्रतिशत अधिक है। पहली बार, केन्द्रीय बजट में रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए अलग से धनराशि का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि रक्षा खर्च में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। यह बात दीगर है कि जब आम आदमी महंगाई से ही मर जाएगा, तो रक्षा किसकी होगी।

ढांचागत विकास पर जोर दिया गया है, और सड़कों तथा तटों के निर्माण के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के तहत, 8,000 करोड़ रुपए

की परियोजनाएं ली जाएंगी, जोकि रेल बजट के प्रावधानों से अतिरिक्त होगा। मुम्बई तथा दिल्ली में दो हवाई अड्डों तथा मुम्बई व कोची के समुद्री बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सड़क निर्माण के 2,600 करोड़ रुपए की पूर्ति के लिए जहां पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया है, वहीं ढांचागत विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका मतलब, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में होने वाली निजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। यह याद रखा जाना चाहिए कि जसवन्त सिंह ने ही 1996 में 13 दिनों के लिए वित्तमंत्री का पद संभालने के बाद, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए दाभोल पावर कम्पनी के साथ काउन्टर गारंटी पर हस्ताक्षर किया था। विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीलिंग काफी बढ़ा दी गई है।

जहां एक ओर आम किसान कृषि आगतों की कीमत वृद्धि का बोझ झेलेंगे, वहीं हाइ-टेक बागवानी और अच्छे परिणाम देने वाली खेती के लिए एक नई केन्द्रीय स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई।

चाय, काफी और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादकों के लाभ के लिए 500 करोड़ रुपए की मूल्य स्थिरीकरण निधि की घोषणा की गई, जो 2003-04 में लागू हो जाएगी।

घाटा :

इस आय और व्यय के ब्यौरे के अनुसार, राजकोषीय घाटा अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत होगा। तुर्की के बाद, यह घाटा दुनिया में सबसे बड़ा घाटा है। वित्तमंत्री ने इस राजकोषीय घाटे पर चिन्ता तो जताई, पर इसे कम करने के लिए न तो वह अमीरों पर कर लादने के पक्ष में है, न ही रक्षा खर्च में कटौती करने को तैयार है।

कौन खुश, कौन दुखी?

इस बजट से स्पष्ट है कि जहां एक ओर बड़े उद्योगों, उच्च मध्यम वर्गों और पूंजी निवेशकों को फायदा होगा, वहीं आम किसानों और आम आदमी पर बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। यदि एशियाई अर्थव्यवस्था की दृष्टी से देखा जाए, तो यहां का सबसे बड़ा उद्योग कृषि है, और उसके बाद कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग के मरणासन्न स्थिति में पहुंच रहे प्रमुख हिस्से, हथकरघा को इस बार भी भुला दिया गया, जबकि पावरलूम कर्मियों को बीमा का झुनझुना पकड़ा दिया गया। सोना तो सस्ता कर दिया, पर पहले से ही यूरिया के दामों में बढ़ोत्तरी और सूखा का संकट झेल रहे किसानों पर खाद का दाम बढ़ाकर और बोझ लाद दिया गया। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर एक बार भारी बढ़ोत्तरी से ट्रैक्टर चलाना व उपज को मंडियों में पहुंचाना महंगा हो गया है। बजट उत्पादन तो नहीं बढ़ाएगा, पर कृषि की लागतें काफी बढ़ा देगा। विदेशी शराब जरूर सस्ती हो गई है, पर गरीबों का घी, वनस्पति, रिफाइंड अचानक तीन रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। यह सच है कि उर्वरकों की मूल्यवृद्धि तात्कालिक तौर पर वापिस ले ली गई है। परन्तु इससे बजट की प्राथमिकताओं में कोई बुनियादी फर्क नहीं होता है। मजबूरी में मूल्यवृद्धि तो वापिस हुई है, पर अभी भी वित्तमंत्री उर्वरकों को दी जाने वाली सब्सिडी से अपनी चिन्ता जताकर खतरे के संकेत दे रहा है।

आयकर राहत सहित कई उपायों से जहां एक ओर मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, खाद तथा कई सेवा करों में वृद्धि से किसानों व आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। बजट में लोक भविष्य निधि और लघु बचत पर ब्याज में एक प्रतिशत की कटौती भी कर दी गई है, जो आम आदमी की बचत पर होने वाली आय को भी घटा देगा। हां, 7.5 लाख रुपए तक की आय कमाने वालों के लिए अधिभार जरूर कम कर दिया गया है। पूंजी बाजार की खुशी की खातिर शेयर और लाभांश पर कर समाप्त करने की घोषणा, विनिवेश की नीति पर जोर तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन के कारण, स्वाभाविक तौर पर देश के प्रमुख उद्योग मण्डलों ने इस बजट को विकासोन्मुख बताया है।

इस बजट को चुनावी बाजीगरी की ही संज्ञा दी जा सकती है क्योंकि इसमें जनता को लुभाने के लिए कुछ आकर्षण भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, इस बजट से साम्राज्यवाद-अनुकूल आर्थिक नीतियों को ही ज्यादा बल मिलेगा जिससे जनता का जीवन-स्तर और भी गिर जाएगा। ऐसे में, जनता के सामने एक ही विकल्प बचता है कि देश के दलाल शासकों द्वारा लागू की जा रही इन नीतियों का दृढ़ता से विरोध करे। साथ-साथ, जनयुद्ध को आगे बढ़ाकर आधार इलाकों की स्थापना करना ही लुटेरे शासकों को मुंहतोड़ जवाब होगा, जहां पर साम्राज्यवादी लूट और सरकार की दिवालिया कर नीतियां लागू न हों। ऐसे इलाकों में पैदा होने वाली तमाम सम्पदाओं को जनता के कल्याण पर ही खर्चा जाएगा, न कि सरकार के राजस्व या अन्य विभागों द्वारा लूटा जाएगा। यही है इन शोषणकारी बजटों का सही और दूरगामी जवाब। ❑

पाठकों से अपील

- **'प्रभात' के लिए भेजी जाने वाली रिपोर्टों को कागज में एक ही तरफ लिखिएगा और मर्जिन जरूर छोड़िएगा। रिपोर्टें अच्छे कागज पर लिखिएगा क्योंकि खराब कागज पर लिखने की वजह से कई रिपोर्टें हमारे पास पहुंचने से पहले ही फट रही हैं।**
- **रिपोर्ट जिस घटना/कार्यक्रम से सम्बन्धित हो, उसके सारे ब्यौरे – यानी घटित तारीख, स्थल, डिवीजन आदि – जरूर लिखें। कृपया इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई साथी रिपोर्टों में घटना की तारीख डालना भूल रहे हैं।**
- **पाठकों के साथ संवाद के बिना पत्रिका का काम अधूरा ही होगा। 'प्रभात' में छपने वाले लेखों और लिखी जा रही भाषा पर आपकी बेझिझक आलोचनाओं, सलाहों और सुझावों का हमें इन्तजार रहेगा।**

- सम्पादकमण्डल

केरल में जलियांवाला बाग

19 फरवरी 2003 को केरल के इतिहास में पुलिस की गोलीबारी की अब तक की घोरतम कार्यवाही में कम से कम 20 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हो गए और 35 महिलाओं तथा 31 बच्चों का अभी तक कोई अता-पता नहीं है। यह एक और जलियावाला बाग काण्ड था जिसे उपनिवेशी शासकों ने नहीं, बल्कि केरल की कांग्रेसी सरकार ने अंजाम दिया। 1980 में आन्ध्रप्रदेश के इन्द्रवेल्ली गांव में पुलिस द्वारा किए गए गोलीकाण्ड से भी इसकी तुलना की जा सकती है। इत्तेफाक से, उस बर्बर कार्रवाई के लिए भी कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार थी, जिसमें कई मासूम आदिवासियों को मौत की नींद सुला दी गई थी। हैरान की बात है कि मुख्यमंत्री एके आन्टोनी ने इस नृशंस गोलीबारी का पूरा समर्थन किया और कहा "ऐसी कार्यवाहियों से सख्ती से निपट लिया जाएगा।"

इस अविश्वसनीय सी लगने वाली क्रूरतम कार्यवाही का जवाब आदिवासियों ने बहादुरी के साथ दिया। नुकीले बनाए डंडों, छुरों, हंसियाओं और तीर-धनुषों से लैस आदिवासियों ने हत्यारे पुलिस से जमकर लोहा लिया। यह लड़ाई उन्होंने जंगल पर अपने अधिकार के लिए की। वह जंगल जिसे सरकार ने 1973 में मुथंगा वन्यप्राणी संरक्षण केन्द्र में बदल दिया था। उस पर 3 जनवरी 2003 को आदिवासियों ने कब्जा कर लिया। पुलिस ने इस जंगल को 'मुक्त' कराने की अपनी कार्यवाही 19 फरवरी को, सुबह के 9 बजे मीडिया की चकाचौंध में शुरू कर दी। यह देखते ही देखते बेहद बर्बर और असंवेदनशील कार्यवाही में बदल गई, खासकर तब जब एजीएस (आदिवासी गोथ्रा सभा) के कार्यकर्ताओं ने एक पुलिस जवान व एक वन अधिकारी को बन्धक बनाया। पुलिस इससे बौखला गई, बर्बरतम हमला शुरू कर दिया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वायनाड के आदिवासियों की कहानी बाहरी लोगों और अनुवर्ती सरकारों, जिसमें माकपा भी शामिल है, द्वारा किए गए शोषण और विश्वासघात की है। वायनाड के कुल एक लाख से ज्यादा आदिवासियों में से 70 हजार भूमिहीन हैं। बाकी लोगों ने, जो मुख्य रूप से कुरिचियर और कुरुमार थे, अपनी जमीनें बाहरी लोगों से लिए गए कर्ज के बदले गंवा दीं।

केरल में जमीन पर अधिकार के लिए आदिवासियों द्वारा लम्बे अरसे से गुहार लगाई जा रही है। लेकिन इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और आदिवासियों को जमीन दिलवाने की कोई कोशिश नहीं की, जिससे कि वे इज्जत के साथ जी सकें। हालांकि 1975 में केरल सरकार द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक बाहरी लोगों द्वारा हड़प ली गई जमीनें आदिवासियों को वापिस दिलवानी थीं। लेकिन कानून को बने 25 बरस बीतने के बावजूद इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसकी वजह यह है कि जिन लोगों से आदिवासियों को जमीनें वापिस करवानी हैं, वे राज्य में शक्तिशाली वोट बैंक माने जाते हैं। इसलिए कांग्रेस और माकपा दोनों गठबन्धन सरकारों ने इस कानून को नहीं लागू करने में ही राजनीतिक रूप से अपनी भलाई समझी।

केरल में वायनाड एक ऐसा इलाका है जहां आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा केन्द्रित है। आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा किए गए एक ताजातरीन सर्वेक्षण के मुताबिक यहां करीब 1.2 लाख आदिवासी आबाद हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान, वायनाड में आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई योजनाओं और आदिवासी कल्याण विभाग के कर्मचारियों के वेतनों पर कम से कम 5.7 करोड़ रुपए खर्चे गए। यह आदिवासियों के लिए प्रस्तावित अनेक कथित लाभकारी योजनाओं के अतिरिक्त था।

इसके बावजूद आदिवासी बहुत गरीबी में जी रहे हैं, यह बात समझने के लिए उनकी बस्तियों पर एक नजर डालना ही काफी है। यहां के प्रमुख आदिवासी कबीले हैं कुरिचियर और पनियार। इनका शानदार इतिहास रहा है। कुरिचियरों ने पझास्सी के राजा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 1805 से करीब नौ सालों तक संघर्ष किया था। एक जमाने में कुरुमारों के पास बहुत सारी जमीन रहा करती थी। लेकिन अब वायनाड के आदिवासियों की सारी शान मिट चुकी है।

जमीन का केरल अनुसूचित जनजाति कानून-1975 को जनवरी 1982 से लागू किया गया, जिसके मुताबिक आदिवासियों की जमीनों को बाहरी लोगों द्वारा खरीदी पर प्रतिबन्ध है और बाहरी लोगों द्वारा हड़प ली गई जमीनों को वापिस देना होगा। इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में भी शामिल किया गया। लेकिन यह कानून कागजों में सिमट गया, अमली रूप नहीं लिया।

एक जनहित याचिका के फलस्वरूप, 1993 में केरल उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह 1975 का कानून लागू करे। उसी समय नल्ला थम्पि नामक वायानाड के एक गैर-आदिवासी ने आदिवासियों के संघर्ष का बिगुल बजाया। 1996 में उच्च न्यायालय ने सरकार को 30 सितम्बर तक मोहलत दी ताकि गैर-आदिवासियों को निकाल दे सके। सरकार ने इसकी प्रतिक्रियास्वरूप 1975 के कानून में संशोधन किया। 1990 के दशक तक वायानाड के आदिवासियों में असंतोष बढ़ गया जहां कुछ नक्सलवादी संगठन सक्रिय थे।

गैर-आदिवासियों ने अपनी राजनीतिक ताकत के बल पर वाम मोर्चा और संयुक्त मोर्चा सरकारों पर दबाव डालकर 1975 के कानून के उन "अव्यावहारिक" प्रावधानों में संशोधन करवाया, जिनके मुताबिक उन्हें अपने कब्जे वाली जमीनों को आदिवासियों को लौटना पड़ सकता था। इसके फलस्वरूप 1996 में केरल विधानसभा में आदिवासियों की जमीनों पर गैर-आदिवासियों के कब्जे को वैधता देने वाला विधेयक लगभग एकमत से पारित किया गया। (सिर्फ एक ही वोट विरोध में पड़ा था।) लेकिन राष्ट्रपति ने इस विधेयक को लौटा दिया। 1999 में एक और विधेयक पारित किया गया जिसके मुताबिक जब किसी अधिवासी (बाहर से आकर बसने वाला) के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन होगी तभी अतिरिक्त जमीन को आदिवासियों को लौटाना होगा। लेकिन केरल उच्च अदालत ने इस विधेयक को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने सर्वोच्च अदालत में अपील की और स्थगनादेश हासिल किया।

सीके जानू की अगुवाई में आदिवासी संगठनों द्वारा आमरण अनशन चलाने के बाद, अक्टूबर 2001 में एके आन्टोनी सरकार ने एक समझौते पर दस्तखत किया, जिसमें यह वादा किया गया कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को कम से कम एक एकड़ जमीन (5 एकड़ तक) दी जाएगी, लेकिन कब्जाधारियों से छीनकर नहीं। इस समझौते से बाहरी लोगों द्वारा कब्जा की गई जमीनों को हासिल करने की आदिवासियों की काफी पुरानी मांग फीकी हो गई। लेकिन यह भी लागू नहीं किया गया। 53,472 परिवारों को भूमिहीन परिवारों के रूप में पहचाना गया। 1 जनवरी 2002 को थोड़ी-बहुत जमीन ढूंढ़ निकाली गई और बांट दी गई, जोकि कुल

"तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं !"

- मुथंगा की घटना पर अरुंधती रॉय का मुख्यमंत्री एके आन्टोनी के नाम पत्र

एक समाज के जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं, जब ऐसा कुछ होता है जो उसकी नैतिकता को सार्वजनिक कर देता है। यह एक ऐसा ही पल है। मुथंगा का अत्याचार केरल के इतिहास में सबसे गरीब, सबसे उत्पीड़ित समुदाय के द्वारा न्याय के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सन्दर्भ को कुचलने के सरकार के प्रयास के रूप में लिखा जाएगा। ये इतिहास में इसलिए लिखा जाएगा, क्योंकि यह केरल के ज्यादातर 'संघर्षों' की तरह सत्ता के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच की तुच्छ लड़ाई नहीं है, यह ताकतवर के खिलाफ सचमुच में असली लड़ाई है। ये वो चीज है, जिससे मिथ बनते हैं। मैं मुथंगा से युंरी गई थी, जहां केरल की पुलिस ने सैकड़ों आदिवासियों पर गोलियां चलाई थीं। मैं सुल्तान बातरी अस्पताल गई, जहां जख्मी लोग भर्ती थे। मैं आदिवासी बस्ती में भी गई। मैं कालीकट जेल भी गई थी तथा सीके जानू, गीतानन्दन से मिली जो पुलिस द्वारा पुरी तरह पीटे जाने के बाद अब ठीक हो रहे थे। इसके अलावा मैंने गोलीबारी के प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात की। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, शिशुओं समेत सैकड़ों लोगों पर गोली चलाना एक ऐसा काम है, जिसके समान इतिहास की बहुत कम घटनाएं हैं। ये जलियांवाला बाग की याद दिलाता है। सरकारी आंकड़ों में मृतकों से संख्या दो बताई गई है, पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह पूरी तरह झूठ है। जिन लोगों से मैंने बात की, उन्होंने काफी अधिक संख्या बताई। कोई भी चीज इस घटना को जायज नहीं ठहराती है। पुलिस का कथन कि उन पर बंधक बनाए जाने का संकट था, कहीं से भी इस घटना को जायज नहीं ठहराता। बातचीत करने के किसी भी प्रयास के बगैर, इस प्रकार गोली चलाना मानव जीवन के प्रति सम्मान के गहरे अभाव को दर्शाता है। केवल आदिवासी जीवन ही नहीं, बल्कि पुलिस वाले और वन अधिकारी के प्रति भी जिन्हें बंधक बना लिया गया था। इससे पहले की सरकारों ने असली मिलिटेन्ट द्वारा किए गए अपहरण और हाइजैकिंग से इस प्रकार नहीं निपटा। उन्हें निश्चित रूप से सजा दी जानी चाहिए, पर इसके लिए आज वहां मौजूद सारे लोगों को, आदिवासी गोथ्रा महासभा को, समूचे आदिवासी समुदाय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अस्पताल में मैंने उन लोगों से बात की, जो जिन्दा बच गए हैं। वे इस बात से घबराए हुए थे कि छोटे बच्चों समेत उनके परिवारों के कई सदस्य 'गायब' हैं। मैं एक आदमी से मिली, उसका बच्चा गोद से तब गिर गया, जब वह पुलिस की लाठियों का शिकार हुआ था। और तब से वह गायब है। यह भी नहीं मालूम नहीं है कि वे मर गए हैं या जिन्दा हैं, या घायल और भूखे ही वन्यप्राणी संरक्षण केन्द्र में छिपे हुए हैं। एक सप्ताह बीत गया है और अभी तक गायब लोगों की सूची बनाकर जेल और अस्पताल में चेक करने का काम और उन्हें आश्वस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। ये लोग अपने प्रिय लोगों की अनिश्चितता और शोक के कारण पत्थर-से हो गए हैं। क्या आप सोच सकते हैं, कि आप उनके स्थान पर होते तो कैसा लगता?

इस बीच पुलिस आदिवासियों को आतंकित कर रही है। पुलिस वाले बस्तियों में घुसते हैं, और मर्दों को गिरफ्तार करके उन्हें पीटते हुए और घसीटते हुए ले जाते हैं। स्पष्ट रूप से उनका इरादा संघर्ष को मिटा देने का है। यह माहिर खिलाड़ियों द्वारा खेला जा रहा बेहम राजनीतिक खेल है, पत्रकारों और केमेरा वालों को डराया धमकाया गया है। गोलीबारी के बाद उस स्थान को 15 घण्टों तक मीडिया के लिए बन्द रखा गया था। इस पुलिस राज का परिणाम है कि आदिवासी काम के लिए जाने में भी डर रहे हैं। लोग उन्हें रोजगार देने से डर रहे हैं। इन सब का कुल असर यह है कि वे अपने गांवों में भूख से मर रहे हैं। आगजनी में उनके राशन कार्ड जला डाले गए हैं। यह तो उस स्थिति से भी बदतर है, जिसने उन्हें अपनी जमीनों के लिए लड़ने पर मजबूर किया था।

मैं यह पत्र इसलिए लिख रही हूं जिससे कि आप उन लोगों को तुरन्त छोड दें, जिन्हें बेबुनियाद इलजाम लगाकर पकड़ा गया है, तथा आप यह सुनिश्चित करें कि वे लोग सुरक्षित अपने गांवों में पहुंच सकें। ज्यादातर लोग अपनी सारी सम्पत्ति खो चुके हैं - उनके पास खाना नहीं है, पानी ले जाने के लिए बर्तन नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं।

इस पूरी घटना तथा उसके परिणामों की रिपोर्टिंग में यह भुला दिया गया है कि यह आमना-सामना, केरल सरकार द्वारा 53,000 आदिवासी परिवारों को दिसम्बर 2002 तक जमीन उपलब्ध करना के वायदे के फलस्वरूप हुआ था। यह 28 वर्षो से चल रहे अक्षम्य दांव-पेंच की शृंखला में एक और कड़ी है। हमारा देश, टूटे हुए सपनों के नुकीले टुकड़ों पर खड़ा है।

श्रीमान् ! आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। आपको इसे बदलना होगा। और जल्दी।

टिप्पणी : *युकलिप्टस के बागान को वापिस लेने के उत्साह में इन्सानों को मारने के अलावा, गोलीबारी के बीच, पुलिस के दस्ते ने पिकनिक मनाई। पर्यावरण-संवेदनशील युद्धभूमि में बिखरे हुए प्लास्टिक के कप और प्लेट एक कहानी कह रहे हैं– राज्य के रक्षकों के इस एक भोज ने हजारों आदिवासी परिवारों के घरों व सम्पत्ति से ज्यादा पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कचरा पैदा किया।*

जरूरत का महज 2.3 प्रतिशत थी। इस तरह ढूंढ़ी गई जमीन का भी महज 1.6 प्रतिशत ही वास्तव में आवंटित किया गया। इससे अगर आदिवासियों का गुस्सा भड़क उठा तो ताज्जुब क्या है?

कोई 50 सालों से आदिवासी अपनी अतिक्रमित जमीनें वापिस दिलवाने की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन वे आर्थिक व राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली दूसरी और तीसरी पीढ़ी के गैर-आदिवासी किसानों को जमीनों से निकाल देने में समर्थ नहीं थे। वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार ने आदिवासियों की मांगों का पुरजोर विरोध किया जिसके कैबिनेट में शक्तिशाली गैर-आदिवासी किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व है।

3 जनवरी 2003 को 2,000 आदिवासी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों ने वन्यप्राणी संरक्षण केन्द्र की जमीन पर कब्जा किया। उन्होंने उस क्षेत्र में 'स्वशासन' की घोषणा की और 'जीने के लिए' खेती काम शुरू किया 'क्योंकि उन्हें जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी।' उन्होंने उस नई बसाहट में गैर-आदिवासियों और सरकारी अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उन्होंने कई नाके खोल दिए ताकि आदिवासियों की जमीन में गैर-आदिवासियों के प्रवेश को रोका जा सके। उनके एक नेता जानू ने कहा : "हम इस जमीन और इस जंगल के मूल निवासी हैं। अब हमें अपनी ही भूमि से अलग कर दिया गया है। यह बेहद क्रूरता है।"

इसके बाद, वन भूमि पर इस तथाकथित अतिक्रमण के विरोध में कुछ 'पर्यावरणवादी' संगठनों, शक्तिशाली गैर-आदिवासियों, जिनका समर्थन सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया है, ने 'आन्दोलन' शुरू कर दिए। फरवरी 17 के आते-आते ये ताकतें ज्यादा से ज्यादा आक्रामक होती गईं। उस दिन आदिवासियों ने कुछ वन अधिकारियों समेत 21 लोगों को बन्दी बनाया, जो जंगल में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि तथाकथित अतिक्रमणकारियों को जंगल से बाहर निकाला जा सके। सभी को पकड़ लिया गया और आदिवासियों की हिरासत में रखा गया। एक रात उन्हें अपनी हिरासत में रखने के बाद आदिवासियों ने उन्हें तब रिहा कर दिया जबकि जिला कलेक्टर द्वारा व्यक्तिगत तौर पर बन्दियों से आग लगाने के सम्बन्ध में बयान दर्ज करवाने की उनकी मांग मान ली गई।

जब आदिवासियों को बाहर निकाल देने की यह घिनौनी कोशिश नाकाम हो गई, स्थानीय गैर-आदिवासियों, पर्यावरणवादियों और राजनीतिक पार्टियों के दबाव में 19 फरवरी को पुलिस ने घातक हमला शुरू किया।

आदिवासियों के खिलाफ प्रतिक्रियावादियों की एकजुटता

पिछले कुछ दशकों में 4 लाख आदिवासियों को अपनी जमीनों से बेदखल किया जाना उस अंग्रेजी नीति की कड़ी ही है कि आदिवासियों से जंगल छीन लो और उसमें मौजूद असीम संपदा से करोड़ों रुपए कमा लो। केरल की वन भूमि बेशकीमती चन्दन, लौंग, इलायची और अन्य मसालों – प्राकृतिक या खेती करके उगाए गए – के लिए जानी जाती है। यह बेशुमार सम्पदा का स्रोत है। मुथंगा जंगल को हाथियों की विशाल बसाहट के रूप में भी जाना जाता है। हाथियों के दांतों से अवैध कमाई करने का भी एक जबर्दस्त जरिया है यह। वन माफिया, बाहरी अधिवासियों और राजनीतिकों (खासकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और माकपा) के शक्तिशाली गठबन्धन ने बेसहारा आदिवासियों का पुरजोर विरोध किया।

इस माफिया गठबन्धन को अभी-अभी नए दोस्त मिल गए – पर्यावरणवादी जो उनकी लूट-खसोट को एक वैचारिक रंग दे सकें। वो पर्यावरणवादी ही थे जिन्होंने मुम्बई के निकट बोरिविलि जंगलों को बचाने के नाम पर करीब एक लाख झोंपड़पट्टीवासी परिवारों को निकाल बाहर करने में आग्रणी भूमिका निभाई थी। वो पर्यावरणवादी ही थे जिन्होंने प्रदूषण के बहाने दिल्ली के करीब एक लाख परिवारों और कई छोटे कारखानों को उजाड़ देने में प्रमुख भूमिका अदा की थी। अब वे फिर एक बार केरल के आदिवासियों के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन मुथंगा वन्यप्राणी संरक्षण केन्द्र में यूकलिप्टस के पौधे (जिनकी गहरी जड़ें उस क्षेत्र के पूरे भू-जल को सोख लेती हैं) लगाने से इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उस प्लान्टेशन से जल-वायु को बेहद नुकसान की कीमत पर बिडला के ग्वालियर रेयान फैक्टरी को कच्चा माल मिल जाता है। सचाई यह है कि जंगलों के असली संरक्षक खुद आदिवासी ही हैं, न कि भ्रष्ट वन अधिकारी और राजनीतिक जो वन माफिया और बाहरी लुटेरों से सांठगांठ करके करोड़ों रुपए कमा लेते हैं।

जैसा कि तमाम आदिवासी अंचलों में देखा गया, आदिवासियों को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। दशकों से चलाए गए शान्तिपूर्ण आन्दोलनों से अब तक कोई खास नतीजा नहीं निकला। जबकि समूची व्यवस्था ही उनके खिलाफ एकजुट है, तो आदिवासियों के सामने हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। यह ताजातरीन हत्याकाण्ड इस अनिवार्यता को दर्शाता है कि आदिवासियों को अपनी मुक्ति के लिए हथियार उठाना ही होगा।

आदिवासियों द्वारा जनयुद्ध की राह अपनाए जाने की आशंका के मद्देनजर, सभी किस्म के राजनीतिक नेता इस इलाके में कूद पड़े और उन्हें ठगने की कोशिशें शुरू कर दीं। माकपा, जिसने पिछले तीन दशकों के दौरान कई बार सत्ता पर काबिज रहते हुए मजबूती से बाहरी लोगों का पक्ष लिया था, अब अदिवासियों के प्रति दिखावटी हमदर्दी जता रही है। आरएसएस ने इस क्षेत्र में घुसपैठ करने की एक बड़ी योजना बनाई ताकि आदिवासियों के क्रान्तिकरण के बजाए संस्कृतकरण किया जा सके। सभी राजनीतिक पार्टियां, यहां तक कि कांग्रेस के कुछ असन्तुष्ट नेता भी इस हत्याकाण्ड से राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये तमाम सत्ता के दलाल वोट पाने के लिए आदिवासियों के खून से धंधा कर रहे हैं।

लेकिन, वायानाड के आदिवासियों की शानदार परम्परा रही है, जिसका जुड़ाव महान नक्सलबाड़ी के इतिहास के साथ रहा। वे अब नक्सलबाड़ी का ही रास्ता अपनाने के लिए विवश हैं जोकि उनकी मुक्ति का एक मात्र रास्ता है। ❑

दमन

पेट्रोल का इंजेक्शन : गड़चिरोली पुलिस का ताजातरीन 'नुस्खा'

क्या आप जानते हैं कि आदमियों को पेट्रोल का इंजेक्शन लगाया जाता है? शायद नहीं! ज्यादातर लोग नहीं जानते! लेकिन यह सच है, गड़चिरोली पुलिस गिरफ्तार लोगों को यह इंजेक्शन लगा रही है। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होता है? और इसे क्यों लगाया जाता है? पट्रोल की सुई लगाने के बाद आदमी का शरीर ऐसा जलता है जिसका बयान करना मुश्किल है। वह दर्द से कराहता रहता है, जबकि इसका मजा लेते हुए पुलिस वाले हंसते रहते हैं। लोगों को जबरन कसूर कबूलवाने के लिए वे यह पाशविक तरीका अपना रहे हैं। सभ्य समाज इसकी कल्पना तक शायद ही करे, लेकिन गड़चिरोली पुलिस के पास ऐसे कई तरीके हैं। **जरा इनके एक-दो पुराने और काफी प्रचलित तरीकों पर भी गौर करें : जीप की इंजन चालू रखना और बॉनेट ऊपर उठाकर उस पर आदमी को नंगा लेटाना; आदमी के हाथ एक रस्सी से बांधना और उसके दूसरे सिरे को पुलिस की जीप के पीछे बांधकर जीप को दौड़ाना; बिजली के झटके लगाना।** गड़चिरोली के गट्टा, भामरागढ़, अहेरी, एटापल्ली, टिप्रागढ़, चामोर्षी.... हर इलाके में जारी पुलिसिया आतंक के तरीके समान ही हैं। लोगों को मारना-पीटना तो मामूली बात है, वैसे पेट्रोल की सुई के सामने यह तो कुछ भी नहीं है। यह सब जिले के एसपी राजवर्धन की अगुवाई में हो रहा है।

ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के पास सिर्फ दमन ही एक मात्र हथियार है। और भी बहुत सारे हैं। वे इधर-उधर से चंद नौजवानों को इकट्ठा कर लेते हैं और 'नक्सलवादियों का आत्मसमर्पण' करवाते हैं। अखबारों में वही छपता है जो पुलिस छापने को कहती है। कुछ गांवों के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और अखबारों में उनकी तरफ से पुलिस ही बयान जारी कर देती है कि फलां-फलां गांव ने नक्सलवादियों को दूर रखने का फैसला कर लिया। वह यहां तक कि लोगों की बैठकें भी लेती है जिसमें 10-12 गांवों से लोगों को बुलाया जाता है। उसमें काफी ढोंगबाजी की जाती है कि नक्सलवादियों से कोई फायदा नहीं है, खुद पुलिस ही सब कुछ कर देगी। यहां तक कि वे दवाइयां बांटने का ढोंग भी कर लेते हैं। यानी ऐसा हर तरीका है उनके पास, जो साम-दान-भेद-दण्ड की श्रेणी में आ जाए। वे गोली मार सकते हैं, पीट सकते हैं, जेल में ठूंस सकते हैं, दवाइयां बांट सकते हैं, पेट्रोल की सुई भी लगा सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं.... आखिर गड़चिरोली पुलिस तो है।

गड़चिरोली में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने एड़ी-चोटी का जोर लगा रखा है। गट्टा रेन्ज में गिल्लनगूडा, मुहंदी, ताडिगुडा और उसके आसपास के गांवों से पुलिस ने पिछले मई में कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया। मोडस्के गांव से चार लोगों को गिरफ्तार किया। इन सबकी बुरी तरह पिटाई की गई। बाद में इनमें से कुछ लोगों को नागपुर और कुछ लोगों को गड़चिरोली के जेलों में रवाना कर दिया गया। ये सब निर्दोष थे, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए। इनमें रामा गोटा नामक एक व्यक्ति भी शामिल था जिसे पुलिस ने तब गिरफ्तार किया जब वह ताड़ के पेड़ के पास गया हुआ था। तीन दिनों तक थाने में इसे बेदम मारा। गांव वाले इसकी तलब करने गए तो पुलिस ने रामा को छुपाया था। बाद में ग्रामीणों ने थाने के सामने धरने देने की धमकी दी तो पुलिस रामा को दवाखाना भेज दिया।

भामरागढ़ तहसील के गुण्ड्रुवाया का टोला, फुलनार पर छापा मारकर पुलिस ने लोगों की तीन भरमार बन्दूकें जब्त कर लीं। घरों में मौजूद चाकू, हंसिया आदि खेती के औजार भी ले गए। एक घर से 400 रुपए भी ले गए। जब वे इस तरह दिन-दहाड़े चोरी कर रहे थे तब गांव के स्त्री-पुरुष बांस काटने जंगल में गए हुए थे। पुलिस को कानून का रखवाला कहा जाता है। शायद ऐसा 'कानून' जो इजाजत के बिना ही किसी के घर में घुसने और घर का नगद-सामान लूटने की छूट पुलिस को देती है।

भामरागढ़ एरिया में मेडपल्ली गांव के पास पामुल-गौतमी नदी पर पुलिया निर्माण एसपी राजवर्धन के लिए जैसे एक चुनौती बन गया। पार्टी तथा जन संगठनों के कहने पर इस इलाके की जनता ने इसका निर्माण करने से मना कर दिया क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है, उलटा नुकसान ज्यादा है। वैसे तो यह तर्क काफी पहले ही रद्द किया जा चुका है कि जंगली क्षेत्रों में सड़क या पुलिया के निर्माण से जनता का विकास होता है। जनता पर दबाव डालकर किसी भी कीमत पर पुलिया बनाने की ठान ले रखी पुलिस ने। एसपी राजवर्धन ने तेन्दुपत्ता तुड़ाई काम बन्द करवाया। उसने ठेकेदारों को धमकी दे डाली कि जो ठेकेदार इस इलाके में पत्ता तुड़वाएगा, उसे 'पोटा' के तहत गिरफ्तार करवाएगा। ऐसी स्थिति में यहां पर पत्ता तुड़वाने के लिए कोई ठेकेदार तैयार नहीं हुए।

अहेरी तहसील के जिम्मलगट्टा क्षेत्र में 'पीपुल्स गेरिल्ला आर्मी के 18 सदस्यों का आत्मसमर्पण' का नाटक भी पुलिस अधीक्षक राजवर्धन के मार्गदर्शन में ही खेला गया। राजवर्धन कहता है : "गड़चिरोली जिले से 500 नक्सलवादियों का आत्मसमर्पण नहीं कराने से मेरा नाम राजवर्धन नहीं।" लोगों को इकट्ठा करके नक्सली बताकर 'आत्मसमर्पण' करवाने का यह तरीका अपनाकर 500 क्या, 5,000 लोगों को भी राजवर्धन आत्मसमर्पण करवा सकता है!

राजवर्धन और उसके दलाल आका एक सचाई को नजरअन्दाज कर रहे हैं। एक ऐसी सचाई जो इतिहास में बार-बार साबित हो चुकी है। **गेंद को जितने जोर से पटकाओगे उतने ही जोर से वह उछलेगी भी और कोई भी व्यक्ति अपनी हथेली को अड़ाकर सूरज की रोशनी को रोक नहीं सकता।** पहले से ही गड़चिरोली जनता की संघर्षमय परम्परा रही है। राजवर्धन के पैदा होने से काफी पहले ही, अंगरेजों के जमाने से ही उन्होंने बगावत का परचम ऊंचा उठाए रखा है। दमन के हर दौर को उन्होंने कुरबानियां देते हुए भी मात दी है। पेट्रोल इंजेक्शन देने जैसी क्रूर हरकतें करते हुए वे खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं, इतिहास उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। ❑

दण्डकारण्य में सीआरपी बलों का आतंक
जनता और पीजीए योद्धाओं का बहादुराना प्रतिरोधी संघर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार पिछले कई महीनों से नक्सलवादियों के साथ शांतिवार्ता की पेशकश करती आ रही है। इसके जवाब में हमारी पार्टी ने अनुकूल माहौल बनाने की एक मामूली शर्त पर बातचीत के लिए सहमति व्यक्त की। लेकिन सरकार ने अनुकूल माहौल बनाना तो दूर, उलटा क्रान्तिकारी आन्दोलन का उन्मूलन करने के लिए भयानक दमन अभियान छेड़ दिया। बस्तर के संघर्षरत इलाकों में पहली बार सीआरपीएफ की दो बटालियनें तैनात करके गांवों और जंगलों में आतंक मचा दिया है। सीआरपी बल सैकड़ों की संख्या में गांवों पर छापेमारियां करते हुए लोगों को बुरी तरह मारना-पीटना, गिरफ्तार करके झूठे मामले दर्ज करना, लोगों के घर जलाना, घरों से पैसे लूटना, शहीदी स्मारकों को तोड़ देना, हवाई फायर – कुछेक बार निहत्थे लोगों पर फायर करके मुठभेड़ की कहानी गढ़ना आदि रूपों में दमन अभियान जारी रखे हुए हैं। स्थानीय पुलिस, एसएएफ और कुख्यात गोपनीय सैनिक इनका साथ दे रहे हैं। नारायणपुर पुलिस जिले में इन आतंकी बलों ने अपने अभियान को 'इन्तकाम-ए-शहीद भास्कर दीवान' का नाम दिया है। याद रहें कि भास्कर दीवान एक कुख्यात पुलिस अधिकारी था जिसने नारायणपुर के निकट कोटेनार गांव में चार क्रान्तिकारियों समेत पांच लोगों की हत्या की थी। उस मानव रूपी पशु को वाकुलवाही के निकट एक ऐम्बुश में क्रान्तिकारी बलों ने मौत के घाट उतार दिया था। उसी का इन्तकाम लेने के इरादे से अब जनता के खिलाफ एक आतंकपूर्ण अभियान छेड़ दिया गया।

पश्चिम और दक्षिण बस्तर डिवीजनों में जून के मध्य तक सीआरपी वालों ने 80 लोगों को गिरफ्तार किया। कई गांवों को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। बलात्कार, मारपीट, आदि घटनाएं आम हो गईं। रास्ते में जो भी मिलता उसके साथ मारपीट करना और भयभीत करने के लिए हवा में फायर करना पुलिस का रोजमर्रा का काम हो गया। उत्तर बस्तर डिवीजन में अप्रैल-जून तक कम से कम 80-90 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीआरपी ने जनता के पास मौजूद कई भरमार बन्दूकें भी छीन लीं। पुलिस महानिरीक्षक पासवान और एसपी भेडिया ने एक योजना के अनुसार ही लोगों पर दमनचक्र चला रहे हैं ताकि क्रान्तिकारी आन्दोलन का उन्मूलन किया जा सके।

उत्तर बस्तर के कोण्डागांव और डौला इलाकों में पुलिस ने कुछ जन-विरोधी व असामाजिक तत्त्वों को इकट्ठा करके उनके जरिए जनता और जन संगठनों के नेतृत्व पर एक आतंकी अभियान छेड़ दिया। कुछ तकनीकी कारणों से इस क्षेत्र में छापामार दस्तों की गतिविधियां स्थगित रखी गई थीं। इसका उन्होंने फायदा उठाया। इस दमनात्मक अभियान में भाजपा के स्थानीय नेतृत्व का भी सक्रिय योगदान रहा। उन्होंने अलग-अलग कोई 10-12 कार्रवाइयों में 60-70 लोगों को बुरी तरह मारा और पीटा। उनकी सम्पत्तियां जब्त कर लीं। घर जला दिए। एक गांव में उन्होंने कॉमरेड सुखदेव के शहीदी स्मारक को तोड़ दिया।

15 अप्रैल को माड़ डिविजन के ग्राम कुंदला में सीआरपीएफ ने छापेमारी की। गांव में स्थित शहीदी स्मारक को तोड़ दिया। मंगलू नामक एक किसान के घर में घुसकर वहां से उनकी तस्वीरें उठाईं। एक और मजदूर को, जो मजदूरी लेने के लिए नारायणपुर जाकर आ रहा था, पुलिस ने खूब मारा और उस पर झूठा मामला दर्ज किया। ग्राम सोनपुर में बीमारी के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन पुलिस ने उसे नक्सलवादियों ने मारा कहकर जबरन उसकी लाश बाहर निकलवाई। एक डॉक्टर को लाकर पोस्टमार्टम करवाया। गांव के 7 निरपराध लोगों को बिना वजह गिरफ्ताकर ले गए। इसी तरह ग्राम कोहकामेट्टा और राणीवेडा में सीआरपीएफ ने आतंक का ताण्डव मचाया।

इन्द्रावती एरिया में सीआरपीएफ वालों ने कई दमनात्मक कार्रवाइयां चलाईं। ताकिलोड गांव में उन पर पीजीए के हमले के बाद तो उनकी बौखलाहट ज्यादा बढ़ गई। ग्राम वेडमा में ऊराल नामक एक किसान पर बिला वजह गोली चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। नीरुम गांव में बोमुडाल नामक एक किसान का घर जलाकर उन्होंने पाशविकता की हद पार की। घर में उसके सारे अनाज और अन्य सामान जलकर राख हो गए। उसकी गलती यही थी कि उसकी बेटी पीपुल्सवार पार्टी में काम करती है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। इस क्षेत्र से कुल 42 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनमें 17 महिलाएं हैं, कुछ तो स्कूल जाने वाली लड़कियां भी हैं। पुलिस वालों ने शिक्षकों को भी नहीं बख्शा। ताकिलोड में जोगाल नामक एक गुरूजी को पुलिस ने बेहद मारा।

दरअसल बस्तर में सीआरपीएफ की तैनाती पहली बार नहीं हुई। इसके पहले भी जब-जब चुनाव हुआ तब-तब सीआरपीएफ की तैनाती होती रही। लेकिन फर्क यह है कि अबकी बार चुनाव के काफी पहले ही इसकी तैनाती हुई, वह भी काफी बड़ी संख्या में और स्थाई तौर पर। लगभग ढाई हजार जवान तैनात कर दिए गए। केन्द्र सरकार के निर्देश में गठित संयुक्त ऑपरेशनल कमान के फैसले के मुताबिक ही केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपी बलों को यहां भेज दिया। इधर अजीत जोगी सरकार ने दो साल पहले ही क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए 1450 करोड़ की कार्ययोजना बनाकर स्वीकृति के लिए केन्द्र के पास भेज रखी है। वह हर बार यह शिकायत भी करती रही है कि केन्द्र सरकार इसका अनुमोदन नहीं कर रही है। अब सीआरपीएफ बलों को तैनात करने के बाद, जोगी ने इसे केन्द्र सरकार का फैसला बताकर खुद को जनता के क्रोध से बचाने की घिनौनी कोशिश की। घोर राजनीतिक संकट में फंसे जोगी की मजबूरी है कि अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में विजय पाने के लिए वह जनता के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता। इसीलिए वह इस तरह की नौटंकी कर रहा है। लेकिन उसके कैबिनेट के अन्य मंत्री तो सीआरपीएफ की तैनाती के फैसले को न सिर्फ सही बता रहे हैं, बल्कि और चार बटालियनें तैनात करने

की मांग भी उठा रहे हैं। इन विरोधाभासी बयानों से परे, जोगी सरकार के दोगलेपन और दमनकारी चरित्र को जागरूक जनता ने अच्छी तरह से समझ लिया। बस्तर के कोने-कोने में ***'सीआरपीएफ को वापिस बुलाओ'*** का नारा बुलन्द हो रहा है।

बस्तर की जनता की शानदार लड़ाकू परम्परा रही है। उन्होंने ब्रितानी उपनिवेशवादी सेनाओं के खिलाफ एक के बाद एक कई विद्रोह किए थे। बस्तर के अनगिनत माटी-पुत्रों ने अपनी धरती को विदेशी दासता से मुक्त करवाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। अब वे सर्वहारा के नेतृत्व में साम्राज्यवाद, दलाल पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ हथियारबन्द संघर्ष कर रहे हैं। अपनी शानदार लड़ाकू परम्परा को आगे बढ़ाते हुए बस्तर की क्रान्तिकारी जनता और पीजीए के लाल सैनिकों ने सीआरपीएफ के खिलाफ भी बहादुराना प्रतिरोधी संघर्ष किया।

पश्चिम बस्तर में जन-प्रतिरोध

- सीआरपीएफ के 50 जवानों ने ग्राम चेरपल्ली में स्थित सरकारी स्कूल में डेरा जमाकर आसपास के गांवों में खोजबीन अभियान चलाने की योजना बनाई थी। पास में मौजूद पीजीए सदस्यों को यह खबर मिली तो तीन सदस्यों ने सादे कपड़ों में जाकर दो ग्रेनेड फेंके। यहां पर सीआरपीएफ वालों के संतरी ने छापामारों को पहले ही पहचान कर गोलीबारी शुरू की थी। दोनों पक्षों में कोई हताहत नहीं हुए, पर पुलिस वाले घबरा गए।
- ग्राम पेद्दा बोडिकेल और इलिंगेर में भी कैम्प डालकर आसपास में खोजबीन अभियान चलाने के इरादे से सीआरपीएफ और एसएएफ का संयुक्त दल आया था। लेकिन उन पर पीजीए के आधार बल के सैनिकों ने हमले कर दिए तो उन्हें अपनी योजना को स्थगित करना पड़ा।
- जेगुरगोंडा एरिया के ग्राम तिप्पापुरम में सीआरपीएफ के जवानों और जनता के बीच झड़प हुई। लोगों ने जुल्मी सीआरपीएफ वालों को पीट दिया। पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया।

उत्तर बस्तर की आदिवासी महिलाओं का शानदार प्रतिरोधी संघर्ष

- जनवरी माह में काकानार इलाके में ग्राम मेस्पी पर सीआरपी ने छापेमारी की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जब वे गिरफ्तार व्यक्ति को लेकर वापिस जाने लगे, तब गांव की महिलाओं ने उनका पीछा किया। उन्हें ग्राम वारकोट के निकट महिलाओं ने घेर लिया और अपने आदमी को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया।
- ग्राम अवालवरसा में सीआरपी आई थी। उनके साथ में एक दलाल भी था जो भूतपूर्व दस्ता सदस्य था। वह पुलिस के साथ रहते हुए ग्रामीणों को पकड़ने और पहचानने में उसकी मदद कर रहा था। गांव की महिलाएं एकजुट होकर पुलिस को घेर लिया। उन्होंने उस गद्दार को अपने हवाले कर देने की मांग की। पर पुलिस किसी तरह खुद को और अपने भाड़े के टट्टू को महिलाओं के क्रोध से बचकर वहां से खिसक गई।
- ग्राम लोहार में भी महिलाओं ने सीआरपी का मुकाबला किया ताकि गिरफ्तार किए गए अपने आदमियों को छुड़ाया जा सके। लेकिन उन्हें इसमें सफलती नहीं मिली। इसी प्रकार हर जगह सीआरपीएफ को जनता और खासकर महिलाओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जैसे कि कैरिपदर, बेटिया आदि गांवों में भी हुआ।
- केसकाल एरिया के ग्राम काडानार (कानागांव) में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सीआरपी वालों ने कुछ लोगों को संघम के सदस्य बताकर गिरफ्तार करने की कोशिश की। वहां उपस्थित महिलाओं ने अपने क्षेत्र के आदमियों को पुलिस के चंगुल से बचाने के लिए बहादुरी के साथ मुकाबला किया। उन्होंने पुलिस को घेरकर सवालों का बौछार की कि उनका कसूर क्या है और क्यों उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद सीआरपी को झख मारकर उन्हें छोड़ देना पड़ा।

पीजीए ने कर दिया सीआरपीएफ वालों के नाकों दम

- 5 मई को पीजीए के गौण बल को यह खबर मिली थी कि सीआरपी और एसएएफ के करीब 80 जवानों ने ग्राम मेस्पी पर हमला कर दिया। तुरन्त ही पीजीए सैनिकों ने उन पर जवाबी हमले की योजना बनाई। एक जगह उन पर घात लगाकर हमला किया। चूंकि वहां की स्थिति अनुकूल नहीं थी, इसलिए पीजीए सैनिक सिर्फ दुश्मन को हैरान करने के इरादे से 3-4 फायर करके वापिस चले गए। लेकिन दुश्मन काफी भयभीत हुआ और काफी देर तक पागलों की तरह फायर करता रहा और दो इंच मोर्टार के गोले भी दागता रहा।
- 6 मई को सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के दो दल, जिनमें क्रमशः 70 और 90 जवान थे, नारायणपुर और धनोरा थानों से गश्त पर निकले थे। ये दो दल एक निश्चित जगह पर एक-दूसरे से मिलकर फिर लौट रहे थे। वे कुछ ग्रामीणों को भी अपने साथ रखे हुए थे ताकि हमले की स्थिति में उन्हें कवच की तरह इस्तेमाल किया जा सके। पीजीए सैनिकों की एक टोली ने इनमें से एक दल पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में एक गोपनीय सैनिक (रामसिंह पोयाम) और एक सीआरपीएफ जवान बुरी तरह घायल हुए। पुलिस के साथ जाने वाले ग्रामीणों को बचकर भागने का मौका मिला और वे दौड़ते हुए छापामारों की तरफ आ गए। पुलिस काफी देर तक अपनी गोलियां और मोर्टार के गोले बर्बाद करती रही जबकि छापामार और ग्रामीण सकुशल निकल चुके थे।
- पीजीए के आधार बल (जन मिलिशिया) के सैनिक भी

सीआरपीएफ का मुकाबला करने में पीछे नहीं रहे। कोइलीबेड़ा एरिया में ग्राम मेस्पी, केसकाल एरिया में ग्राम गवाडी और ग्राम जुंगनार के निकट मिलिशिया की टुकड़ियों ने अपनी भरमार बन्दूकों से सीआरपीएफ पर अलग-अलग हमले किए। उनका मुख्य उद्देश्य था उसे हैरान-परेशान करना, जो कि काफी हद तक सफल हुआ।

पिडियाकोट में सीआरपीएफ की नींदें उड़ीं- *एक जवान घायल*

30 जून को पिडियाकोट गांव में सीआरपीएफ वालों ने एक स्कूल में डेरा डाला था। उन्हें पहले से ही यह आशंका थी कि उन पर पीजीए का हमला हो सकता है। इसलिए उन्होंने काफी संख्या जुटा ली। वे कुल 90 जवान थे, और कमान जिले के एसपी गौतम ने खुद ले रखी थी। वे स्कूल बंगले के भीतर सोए थे। और आते-आते रास्ते में जो भी मिला उसे गिरफ्तार कर अपने साथ रख लिए थे, ताकि उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद भी वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। रेत की बोरियां तैयार करके बंगले के चारों तरफ मोर्चे बनाए। बंगले की छत पर भी रेत की बोरियां जमाकर उसके पीछे छिपकर पहरेदारी कर रहे थे। इन तमाम एहतियाती कदमों के बावजूद वे पीजीए के हमले से बच न सके।

पीजीए को उनकी हर गतिविधि और हर हलचल की खबर थी। 13 सदस्यों की एक छोटी सी टुकड़ी ने कैम्प के नजदीक तक जाकर अचानक तेजी से गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें संतरी में तैनात सीआरपीएफ का एक जवान (जेके मण्डल) बुरी तरह घायल हो गया। करीब 25-30 गोलियां खर्च कर छापामार जल्दी ही पीछे हट गए। लेकिन पुलिस वाले भोर तक करीबन 1,000 गोलियां चलाईं। मोर्टार के 12 गोले दागे सो अलग। इस घटना ने जहां एक ओर सीआरपीएफ का मनोबल बुरी तरह गिरा दिया, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र की जनता को उत्साहित किया।

भैरमगढ़ में मिलिशिया के हमले में एक पुलिस जवान की मौत

बस्तर में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने के अभियान के तहत महेन्द्र कर्मा, राजेन्द्र पामभोई जैसे प्रतिक्रियावादी नेताओं ने पिछले फरवरी से कई स्थानों का दौरा करके कई सभाएं कीं। इसी सिलसिले में 18 मार्च को पश्चिम बस्तर डिवीजन स्थित भैरमगढ़ में राजेन्द्र पामभोई का कार्यक्रम होने वाला था। उसकी

ताकिलोड में पीजीए का हमला

दो सीआरपी जवान मरे और दो घायल

सीआरपीएफ को करारा झटका माड़ डिवीजन के ग्राम ताकिलोड में तब लगा जब वह वहां आतंक का तांडव मचा रही थी। यूं तो ताकिलोड माड़ डिवीजन के अंतर्गत आता है, लेकिन सरकारी हिसाब से यह भैरमगढ़ तहसील (दन्तेवाड़ा जिला) में आता है। दरअसल 22 अप्रैल को इस क्षेत्र के सभी गांवों में पार्टी का जन्मदिन और साथ ही साथ, महान मार्क्सवादी शिक्षक लेनिन का जन्मदिन मनाने की तैयारियां हो रही थीं। एक अज्ञात स्थान पर एक बड़े आयोजन की योजना भी बनाई गई थी, जिसकी सूचना सिर्फ जनता को ही थी, जबकि जनता के दुश्मनों को और उनके भाड़े के सैन्य बलों को इस बारे में कोई इत्तला नहीं थी। इस क्षेत्र में जारी आन्दोलन को आतंक के सहारे कुचलने की नीयत से सीआरपीएफ के करीब 40 जवान ताकिलोड में आए हुए थे। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इन भाड़े के सैनिकों का साथ दे रहे थे स्थानीय भैरमगढ़ थाने के पुलिस अधिकारी। ज्यों ही उन्होंने इन्द्रावती नदी को पार किया, तभी से उन्होंने आतंक मचाना शुरू किया। बैल गांव में, जो इन्द्रावती नदी के तट पर स्थित है, तीन किसानों की पिटाई कर दी। बाद में वे ताकिलोड की ओर बढ़े। ताकिलोड में सबसे पहले जन संगठन के एक कार्यकर्ता के घर पर छापेमारी की। वह घर पर नहीं था। घर से करीब 1400 रुपए और कुछ जेवरात लूट लिए। गांव में मौजूद शहीदी स्मारक को, जो कॉमरेड्स श्याम, महेश और मुरली की याद में निर्मित किया गया था, तोड़ दिया। गांव में जो मिला उसे मारने लग पड़े। गांव में लोगों की एक धान की चक्की थी, उस पर भी पुलिस वालों ने कहर बरपा। उसे जला डाला। दिन भर गांव में पुलिस का आतंक चलता रहा। बाद में उन्होंने गांव में मौजूद स्कूल में डेरा जमाया। ग्रामीण इधर-उधर दौड़-भाग करने लगे।

यह खबर पास में मौजूद पीजीए की एक प्लटून को मिली थी। प्लटून के साथ एक स्थानीय छापामार दस्ता भी था। उन्होंने पार्टी का जन्मदिन मनाने की तैयारियां स्थगित कर दीं। तुरन्त ही आतंकी पुलिस को सबक सिखाने का निश्चय किया। जनता की सक्रिय मदद से रात के 2 बजे करीब 30 छापामारों ने पुलिस वालों के मुकाम पर धावा बोल दिया। करीब 15 मिनट तक उन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी की जिसमें सीआरपीएफ के दो जवान मारे गए और दो घायल हो गए। पुलिस वाले कुछ देर बाद संभल गए और जवाबी गोलीबारी शुरू की। सुबह तक गोलियां चलाते ही रहे और बीच-बीच में मोर्टार के गोले बरसाते रहे। लेकिन छापामार तब तक अपना हमला रोककर काफी दूर चले जा चुके थे जो उनकी रणनीति का हिस्सा था।

उन्होंने पुलिस वालों को ऐसे जाल में फंसा दिया कि मारे गए और घायल पुलिस वालों को वापिस ले जाना एक टेढ़ी खीर बन गया था। एक रास्ते से उन्होंने लाशों को लेकर जाने की कोशिश की, पर वहां पर छापामारों की एक टोली ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। बाद में उन्होंने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की तो वहां भी छापामारों ने उन पर हमला कर दिया। वे इतना घबरा गए थे कि बन्दूक की नोंक पर काफी संख्या में आम लोगों को इकट्ठा करके उन्हें कवच के रूप में इस्तेमाल करते हुए चले गए। ❑

सुरक्षा में काफी संख्या में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई थी। ये पुलिस वाले बाजार में आने वाले लोगों को डराना-धमकाना, उनसे जबरन शराब लेकर पी लेना, आदि हरकतें कर रहे थे। इनके जुल्मों पर रोक लगाने के इरादे से मिलिशिया की एक छह सदस्यीय टुकड़ी ने यहां पर हमला करने का फैसला किया। राजेन्द्र पामभोई की सुरक्षा में आए चार पुलिस वाले जब एक होटल में खाना खाकर बाहर निकल रहे थे, तब उनमें से एक पर मिलिशिया की ऐक्शन टीम ने हमला बोल दिया। चाकुओं से की गई मार से वह बुरी तरह घायल हुआ था। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पामभोई अपना कार्यक्रम तुरन्त रोककर आनन-फानन वहां से भाग गया। इस कार्यवाही के बाद पुलिस वालों में हड़कंप मच गई क्योंकि इस क्षेत्र में मिलिशिया द्वारा लगातार हमले किए जा रहे थे। फरवरी में इन्होंने एक पुलिस को घायल करके उसकी एक रायफल भी छीनी थी। ऐसी कार्यवाहियों से जनता और जन मिलिशिया का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ रहा है और वे जनयुद्ध में ज्यादा सक्रिय रूप से भाग लेने लगे हैं।

कोण्डागांव एरिया में जन-विरोधियों पर क्रान्तिकारी जनता का जवाबी हमला

पिछले साल के मार्च से कोण्डागांव एरिया में कुछ तकनीकी कारणों से छापामार दस्ते की गतिविधियां अस्थाई तौर पर रुक गई थीं। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए इस क्षेत्र के कुछ जन-विरोधी व असामाजिक तत्त्वों ने जनता और जन संगठन कार्यकर्ताओं पर कई हमले कर दिए। इस क्षेत्र में जन संगठनों के हावी होने के बाद पुराने परम्परागत मुखियाओं और भूमिपतियों का वर्चस्व समाप्त हो चुका था। गांवों पर उनका आधिपत्य को चोट पहुंची थी। यहां तक कि जनता ने झूठी सरकार को नकार कर अपने विकास के कार्यक्रम भी जन संगठनों की अगुवाई में चलाए थे। लेकिन जब से यहां क्रान्तिकारियों की गतिविधियां रुक सी गईं, तब से उन्होंने अपना वर्चस्व दोबारा कायम करने का एक अभियान छेड़ दिया। पुलिस वालों से उन्हें पूरा समर्थन हासिल था ही, साथ-साथ भाजपा भी इस क्षेत्र में पैर पसारने के चक्कर में थी। सब मिलकर एक गिरोह बनाया। इस गिरोह के प्रमुख सदस्य थे – रामदेर (डीएकेएमएस का एक भूतपूर्व नेता); कीत्रु और मेघनाथ (दोनों भी पुलिस के मुखबिर थे); सोमारू (स्थानीय भाजपा नेता) और ग्राम मंगवाल का सरपंच। उन्होंने कई गांवों में जन संगठन कार्यकर्ताओं और पार्टी के समर्थकों पर हमले करके बुरी तरह मारा-पीटा। ग्राम कज्जुम में शहीद नेता कॉमरेड सुखदेव की याद में बनाए स्मारक को भी इस गिरोह ने गिरा दिया।

इस साल के मई से जून तक इस गिरोह के खिलाफ जवाबी हमला छेड़ दिया गया। स्थानीय दस्ते के साथ-साथ पीजीए की एक प्लटून ने भी इस अभियान में भाग लिया। सैकड़ों-हजारों लोगों ने इस अभियान के तहत आयोजित सभाओं में भाग लिया। जनता के फैसले के मुताबिक ही इस गिरोह के कुछ कट्टर सदस्यों को सजाएं दी गईं। रामधर को जन पंचायत में पीटा गया। कीत्रु और मेघनाथ गांव छोड़कर भाग गए। जबकि कुछ अन्य जन विरोधियों ने जनता से क्षमायाचना की। इस अभियान से इस क्षेत्र में फिर से क्रान्तिकारी माहौल निर्मित हो गया और जन विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। ❑

आमाबेड़ा हाट बाजार में पीजीए सैनिकों का हमला : *एक पुलिस की मौत और एक एसएलआर जब्त*

एक तरफ बस्तर में सीआरपीएफ की तैनाती शुरू हो चुकी थी और उन्हें नक्सलवादियों से मुकाबला करने में प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तो दूसरी ओर पीजीए सैनिकों ने शत्रु बलों के खिलाफ अपने हमलों का सिलसिला बराबर जारी रखा हुआ था। मुख्य, गौण व आधार बलों के सैनिक अलग-अलग व मिली-जुली कार्यवाहियां करते ही रहे। दक्षिण बस्तर से लेकर उत्तर बस्तर तक हर डिवीजन में, हर क्षेत्र में आए दिन किसी न किसी कार्रवाही की खबरें आती ही रहीं। उत्तर बस्तर में 26 मार्च 2003 को उत्तर बस्तर डिवीजन के केसकाल एरिया के आमाबेड़ा में पीजीए सैनिकों की एक चार सदस्यीय एक्शन टीम ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जो अपने आप में बेमिसाल है। यह टीम गौण व आधार बलों के सदस्यों से बनी एक साझी टीम थी, जिसमें आधार बल के सदस्य ही ज्यादा थे। आमाबेड़ा एक छोटा सा कस्बा है जहां पर पुलिस थाना मौजूद है। यहां हर बुधवार साप्ताहिक बाजार लगता है। इस बाजार में गश्त करने करीब 15 पुलिस वाले थाने से आ जाते हैं और इधर-उधर दारू लूटकर पीते हैं तथा विरोध करने वाले लोगों को डरा-धमकाकर चुप करा देते हैं। हाल के दिनों में तो पुलिस का आतंक जोरों पर चलने लगा था। इस थाने के पुलिस वाले गांवों पर छापेमारी करके लोगों को गिरफ्तार करना, मारपीट करना, जेल भेजना, झूठे केसों में फंसाना, आदि दमनात्मक कार्यवाहियां बड़े जोर से कर रहे थे।

पीजीए की एक्शन टीम का इरादा साफ था – एक तो पुलिसिया आतंक पर अंकुश लगाना और पीजीए के पास हथियारों की जो कमी है उसकी पूर्ति कर लेना। वह ऐसा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी जिसमें बन्दूक छीनने की संभावना रहती हो। इसके मुताबिक योजना बनाई गई। चारों सदस्य सादे कपड़ों में और चाकू जैसे छोटे हथियारों से लैस हो गए। वे बाजार में गए और पुलिस की एक-एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। एक होमगार्ड और एक एसएएफ जवान अपने बाकी साथियों से कुछ दूर थे। होमगार्ड एक घर में घुसकर दारू पीने में मशगूल था, जबकि एसएएफ जवान एक जगह बैठकर आराम फरमा रहे था। पीजीए सैनिक मधुमक्खियों की तरह एसएएफ जवान पर ऐसे झपट पड़े थे कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला था। चाकुओं की मार से उसने बिना रोए-चिल्लाए ही दम तोड़ दिया। उसकी एसएलआर छीन ली और गोलियां भी। होमगार्ड बाहर निकला और बात को समझा, भाग गया। पीजीए सैनिकों ने अपनी कार्यवाही को शानदार ढंग से अंजाम देकर आसपास के गांवों की जनता में उत्साह का संचार कर दिया। ❑

अकाल से निपटने के लिए जनता का सामूहिक प्रयास

दण्डकारण्य की जनता आधार इलाके के लक्ष्य से अपनी राजसत्ता कायम करने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रही है। लुटेरी सरकार के झूठे विकास कार्यक्रमों का पर्दाफाश करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद ही पहलकदमी कर रही है, जिसकी अनेक मिसालें देखी जा सकती हैं। हाल ही में माड़ डिवीजन के अन्तर्गत इन्द्रावती एरिया में अकाल की मार से जूझ रही जनता ने सामूहिक प्रयास के जरिए न सिर्फ समस्या को हल कर लिया, बल्कि ऐसे निर्माणात्मक कदम भी उठाए कि भविष्य में अकाल की मार से बचा जा सके।

इस एरिया में मौजूद जन संगठनों की अगुवाई में यह फैसला लिया गया कि आसपास के गांवों में स्थित भूमिपतियों और धनी किसानों से अकाल चंदा के तौर पर धान वसूला जाए। इस तरह तीन गांवों – बेलनार, गुण्डेमड्डुगु और जाडका में जिनके पास अतिरिक्त अनाज है, उनसे चंदा वसूला गया। बाद में जिन परिवारों में अनाज का अभाव है, उनका हिसाब लगाकर प्रत्येक परिवार को 10 से 15 पायली धान बांट दिया गया। जन संगठनों ने यह भी फैसला किया कि इस अनाज के बदले सामूहिक श्रम करके तालाबों का निर्माण किया जाए। इस तरह अकाल पीड़ित जनता को न केवल राहत पहुंचाई गई, बल्कि भविष्य में अकाल की स्थिति को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इन तीनों गांवों में एक-एक तालाब का निर्माण भी हो गया। जबकि लुटेरी सरकार ने अपनी बहु-प्रचारित 'काम के बदले अनाज' की योजना के तहत लाखों रुपए बहाकर भी जनता के लिए काम आने वाले तालाब का निर्माण कहीं भी नहीं किया और उलटा बीच के दलाल ही पूरा अनाज खा गए, वहीं जनता ने एक छोटे से रचनात्मक कदम से असली विकास का एक नमूना पेश किया।❑

पुलिसिया दमन के खिलाफ मानपुर में जन संघर्ष

मानपुर पुलिस थाने को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस पर 1996 में छापामारों ने एक सफल हमला किया था और सारे हथियार छीने थे। अब फिर एक बार मानपुर पुलिस थाना चर्चा के केन्द्र में है, लेकिन दूसरे कारणों से। मानपुर राजनांदगांव जिले में बसा हुआ एक कस्बा है। लेकिन संगठन की दृष्टि से यह महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले से सटा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गड़चिरोली आन्दोलन के तहत क्रान्तिकारी गतिविधियां चलती रहती हैं। यहां की पुलिस न सिर्फ छत्तीसगढ़ के गांवों में, बल्कि महाराष्ट्र के गांवों में भी लोगों का दमन करते रहते हैं। वैसे तो यह सब केन्द्र सरकार के नेतृत्व में बनी संयुक्त ऑपरेशनल कमाण्ड के तहत ही चलता है जिसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत कई दूसरे राज्य भी शामिल हैं।

मानपुर पुलिस इस क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुकी थी। लोगों को नक्सलियों के साथ सम्बन्ध होने के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर यातनाएं देना, मारना-पीटना, सड़क पर गुजरने वाले वाहनों को रोककर अवैध वसूली करना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, आदि कई प्रकार की ज्यादतियां करती रही। पुलिस ने गांव मर्कानार, तेरेगांव और उच्चापुर से तीन युवकों को नक्सली बताकर गिरफ्तार किया और उन्हें खूब यातनाएं दीं। इसके खिलाफ जनता में जबर्दस्त आक्रोश था। इसलिए जनता ने पुलिसिया दमन के खिलाफ 30 जनवरी को एक विशाल रैली निकालने का फैसला किया। इस सम्बन्ध में आसपास के सभी गांवों में प्रचार अभियान चलाया गया। 30 तारीख की सुबह से ही लोगों का मानपुर पहुंचना शुरू हो गया। पुलिस ने जगह-जगह लोगों को रोकने की कोशिश की। लोगों के ट्रैक्टर आदि वाहनों को जब्त कर लिया गया। इसके बावजूद दोपहर तक करीब 40 गांवों से कोई 8-10 हजार लोग पहुंच चुके थे। जनता का आक्रोश और भी बढ़ गया। उन्होंने थाने को घेर लिया। जनता और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसमें कुछ ग्रामीणों के साथ-साथ दो-तीन पुलिस वाले भी घायल हो गए। पुलिस ने लोगों को भयभीत करने और तितर-बितर करने के लिए हवा में दो गोलियां भी चलाईं। लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक फर्लांग लम्बी रैली निकालकर थाने को पुरी तरह से घेरकर करीब 8-9 घण्टों तक पुलिस वालों को बाहर निकलने नहीं दिया। जनता ने गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग की। और जब्त किए गए तीनों वाहनों को भी छोड़ने की मांग की। पुलिस ने वाहनों को बिना किसी कार्यवाही के ही छोड़ दिया, पर गिरफ्तार लोगों को एसपी से चर्चा करके कार्यवाही के बाद रिहा करने की बात कही। लेकिन लोगों में उत्तेजना और भी बढ़ गई। वे गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग पर अड़े रहे।

इस बीच लोगों ने उत्तेजित होकर शराब भट्टी को पुरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया और शराब के ड्रम, कैन, बोतलें आदि को तोड़-फोड़ दिया। लोगों की मांगों में से एक थी – उन दो पुलिस जवानों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए जिन्होंने विगत 22 जनवरी को मनाय बाई और असामा बाई नामक दो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था। शाम तक पुलिस के आला अधिकारी मानपुर पहुंचे और जब उन्होंने लोगों की मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया, तभी जनता ने अपना संघर्ष समाप्त किया।

गौरतलब है कि मानपुर से थोड़ी ही दूर पर स्थित एक कस्बा

चिचोला में 14 जनवरी को 'नक्सली विरोधी रैली' निकाली गई थी। अखबारों में इसकी चर्चा भी हुई थी। बाद में उसकी पोल तब खुल गई जब उसमें भाग लेने वाले कुछ लोगों ने अखबार वालों को बताया कि उन्हें पुलिस ने गुमराह कर रैली में शामिल करवाया था और कि वे नक्सलवादियों का विरोध नहीं करते। उस कथित 'नक्सली विरोधी रैली' के ठीक सोलह दिन बाद पुलिस के खिलाफ यह विशाल रैली निकली जिसने एक संघर्ष का रूप धारण कर लिया। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि इस क्षेत्र की जनता क्रान्तिकारी आन्दोलन के पक्ष में है और 'नक्सली विरोधी रैली' महज पुलिस की सृष्टि थी। ❑

जन विरोधी अशोक सोरी का सफाया

माड़ डिवीजन के इन्द्रावती एरिया, गीदम विकासखण्ड का एक गांव है तुमनार। यहां अशोक सोरी नामक व्यक्ति ग्राम सेवक और पंचायत सचिव के तौर पर पिछले आठ सालों से काम कर रहा था। इसका ताल्लुक महेन्द्र कर्मा के साथ था जो बस्तर के क्रान्तिकारी आन्दोलन का एक नम्बर दुश्मन है। इसने गांव पर अपना दबदबा कायम करके जन विरोधी गतिविधियां शुरू कर दीं। गांव में बैठने वाले हाट बाजार पर इसका ही प्रभुत्व हुआ करता था। बाजार में बेचे जाने वाले हर बकरे पर यह 10 रुपए वसूला करता था। बाजार में आने वाले व्यापारियों से भी यह अवैध वसूली करता था। गांव की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के लिए भी यह बदनाम था। इसके खिलाफ बोलने पर जान से मार दिया करता था। इस तरह इसने तीन लोगों को मार डाला और पुलिस के साथ सांठगांठ करके मामलों का रफा-दफा करवाया। सरकार की ओर से झूठे सुधार कार्यक्रमों पर आने वाले पैसों में हेराफेरियां करके लाखों रुपए कमा लिए।

पिछले साल तुमनार हाट बाजार में जन संगठन के नेतृत्व में किसानों की फसलों को वाजिब दाम देने के मुद्दे पर व्यापारियों के साथ चर्चा हुई थी। इसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने बाजार को लूटकर बदनामी क्रान्तिकारी जन संगठनों पर डाल दी। उन असामाजिक तत्वों को अशोक सोरी का समर्थन प्राप्त था। बाजार लूटकाण्ड के बाद पुलिस के साथ मिलकर इसने कई लोगों को गिरफ्तार करवाया। उन्हें पुलिस द्वारा यातनाएं दिलवाईं। बाद में यह नियमित रूप से गीदम के पुलिस थाने से सम्पर्क बनाकर मुखबिरी करने लगा। इसे स्थानीय छापामार दस्ते ने दो बार चेतावनी दी कि जन विरोधी गतिविधियां बन्द करे। लेकिन इससे यह नहीं सुधरा। आखिरकार जनता ने इस जन विरोधी को मौत की सजा करार दी। पीजीए के सभी बलों के करीब 40 लाल सैनिकों ने 26 मई को तुमनार में इसके घर पर धावा बोल दिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। इस घटना से इस क्षेत्र के जन-दुश्मनों में दहशत भर गई। ❑

पश्चिम बस्तर की जनता ने गांजे की फसल को ध्वस्त किया

पश्चिम बस्तर डिवीजन के भैरमगढ़-गंगलूर इलाके के ग्राम आवनार का भूतपूर्व सरपंच पूनेम गल्लाल गांजे की फसल उगाकर उसे बेचा करता था। बीजापुर के कुछ अवैध व्यापारी इसे गांजे के बीज देकर फसल उगाने को प्रोत्साहित किया करते थे। पैसे के लालच में गल्लाल ने गांजा उगाना शुरू किया और गुप्त रूप से बेचने लगा। इसने अपने इस धंधे में कुछ दूसरे लोगों को भी जोड़ लिया। जनता ने इसका पता लगाकर स्थानीय पार्टी से इस बारे में शिकायत की। पार्टी ने गांजे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जनता को समझाकर उन्हें सुझाव दिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें।

20 फरवरी को जन संगठन के नेतृत्व में 100 लोगों ने गल्लाल के खेत में जाकर गांजे के सारे पौधे उखाड़कर जला दिए। बाद में पूनेम गल्लाल और उसके दो सहयोगियों को जन अदालत में बुलाई गई। जनता के सामने उन्होंने अपनी गलती मान ली। जनता ने इसे पहली गलती समझकर उन्हें माफ कर दिया और चेतावनी दी कि आइंदा यह धंधा करने से कड़ी सजा मिल सकती है। इस मौके पर उपस्थित लोगों को जन संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तार से समझाया कि गांजा उगाने से क्या-क्या नुकसान होंगे। उन्होंने बताया कि खासकर बस्तर क्षेत्र में गांजे के चोर व्यापारियों, पुलिस अधिकारियों और नेताओं की सांठगांठ से एक गांजा माफिया सक्रिय है। एक तो गांजे के सेवन से लोगों को शारीरिक व सामाजिक रूप से तो नुकसान होंगे ही, इसके अलावा इसे बढ़ावा देने के पीछे एक बड़ी साजिश भी है जिससे आगे चलकर क्रान्तिकारी आन्दोलन के सामने कई मुश्किल चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि गांजे के धंधे के खिलाफ सख्त कदम उठाकर उसका जड़ से सफाया कर दें। ❑

शिक्षा कर्मचारियों के न्यायिक संघर्ष का समर्थन करें !

पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ के शिक्षा कर्मी व शिक्षा गारन्टी गुरूजी अपनी समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार हर साल पुलिसिया दमन और झूठे आश्वासनों से उनके संघर्ष को कुचलती और गुमराह करती आ रही है। इस बार शिक्षा-सत्र के शुरू होते ही शिक्षा गारन्टी गुरूजियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर आन्दोलन छेड़ दिया। राजीव गांधी शिक्षा मिशन को बन्द किए जाने से उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। शिक्षा कर्मियों की वेतन बढ़ाने की मांग भी आज तक पूरी नहीं हुई। प्रदेश सरकार उनकी समस्याओं का समाधान किए बिना ही शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिना रही है। हम छत्तीसगढ़ सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं और गुरूजियों की मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग करते हैं। हम प्रदेश के सभी तबकों की जनता से और खासकर छात्र-छात्राओं और शिक्षक समुदाय से अपील करते हैं कि शिक्षा गारन्टी गुरूजियों और शिक्षा कर्मियों के जायज आन्दोलन का समर्थन करें तथा उनके आन्दोलन के समर्थन में स्कूलों का बहिष्कार करें।

- दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

बिहार-झारखण्ड में पीजीए के शानदार हमले

एक तरफ भीषण शत्रु-दमन को झेलते हुए भी, बिहार में पीजीए के छापामारों ने वर्ष 2003 में सरकारी पुलिस बलों पर कई बहादुराना हमले किए। दूसरी ओर एमसीसीआइ के लाल योद्धाओं ने भी कई जबर्दस्त हमले किए। जन छापामारों के हमलों से शासक वर्गों के दिलों में हड़कंप मची हुई है। लेकिन अपने बलों की शर्मनाक पराजय को छिपाने के लिए पुलिस अधिकारी आए दिन उलटी-सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि पीजीए के हमलों की सफलता का श्रेय उन जानबाज़ जन सैनिकों को जाता है जिन्होंने न सिर्फ बहादुरी का उम्दा प्रदर्शन किया, बल्कि अपना खून बहाकर इन हमलों को सफल बनाने की कोशिश की। उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करते हुए कुछेक हमलों के बारे में विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश करें, जिसकी रिपोर्ट हमें देर से प्राप्त हुई।

पीजीए का 'ऑपरेशन बारा' :
बिहार पुलिस के 'ऑपरेशन समापन' का मुंहतोड़ जवाब

बिहार पुलिस के महानिदेशक बहुत ही उतावला होता जा रहा था। पिछले साल के आखिर में उसने यह ऐलान भी किया कि उसके 'ऑपरेशन समापन' को सफलता मिली है और नक्सलवादी आन्दोलन को काफी धक्का लगा है। लेकिन पीजीए छापामारों ने अपने अन्दाज में इसका जवाब दिया – 'ऑपरेशन बारा' से।

पटना जिले के नौबतुपर पुलिस थाने के अन्तर्गत आने वाला एक गांव है बारा। यहां एक पुलिस कैम्प बिठाया था शासक वर्गों ने, अपने सामंती दोस्तों के बचाव में। लेकिन 23 जनवरी को यहां जो घटना घटी, अब वह इतिहास में अंकित हो चुकी है। रात के अन्धेरे में करीब 40 पीजीए सैनिकों ने थाने को चुप-चाप घेर लिया। कैम्प की छत पर दो संतरी मौजूद थे। सबसे पहले उन्हीं को निशाना बनाते हुए हथगोले फेंके गए, और हमला शुरू हो गया। छापामारों ने बार-बार पुलिस को चेताया कि उनका इरादा उन्हें मारना नहीं, बल्कि बन्दूकें छीनना है ताकि पीजीए की सशस्त्र ताकत में इजाफा किया जा सके। उन्हें समझाया गया कि हथियार डाल दें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन चार घण्टों तक हमला चलता ही रहा। छापामार भारी पड़ गए। कैम्प के दो कमरों को विस्फोट से उड़ा दिया उन्होंने। एक हवलदार मारा गया। छत को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था, सिवाए आत्मसमर्पण करने के।

.303 की 16 रायफलें और एक स्टेन कार्बाइन पीजीए ने पुलिस वालों से छीन ली। साथ ही, 584 गोलियां और एक वायरलेस सेट भी छीन ली। पीजीए के लाल योद्धाओं ने घायल पुलिस वालों की मरहम-पट्टी की और उन्हें समझाया कि उनका राजनीतिक मकसद क्या है। लेकिन इस हमले को सफल बनाने के लिए कॉमरेड सुबोध (25) ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। सुबोध एक नौजवान जन सैनिक था जिसने इस हमले में प्रधान असाल्ट ग्रुप के सदस्य के रूप में भाग लिया। जब उसकी मृत्य हुई वह विशेष छापामार दस्ते के उप-कमाण्डर की जिम्मेदारी में था। हर संघर्ष कुरबानी के रूप में कीमत मांगता है, यह युद्ध का एक द्वन्द्वात्मक नियम है। आइए, 'ऑपरेशन बारा' को सफल बनाने वाले तमाम लाल योद्धाओं को क्रान्तिकारी बधाई दें और शहीद सुबोध के सपनों को पूरा करने का संकल्प लें।

मगध क्षेत्र में पीजीए की एक और सफल रेड

बिहार के मगध इलाके को क्रान्ति का गढ़ कहें तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। साथ ही, वह एक ऐसा इलाका भी है जहां लड़खड़ाती सामंती व्यवस्था को टिकाए रखने का निरर्थक प्रयास कर रही प्रतिक्रियावादी रणवीर सेना की गतिविधियां भी चलती रहती हैं। इन भाड़े के टट्टुओं की रक्षा करने इस क्षेत्र में जगह-जगह पुलिस कैम्प बिठाए जा चुके हैं।

गया जिले के कोंच पुलिस थाना अन्तर्गत लोदिपुर गांव रणवीर सेना का एक मजबूत किला है। यहां पर दो दर्जन पुलिस वालों से एक पुलिस कैम्प बिठाया गया है। इससे रणवीर सेना को क्रान्तिकारियों के हमलों से सुरक्षा मिल रही थी। इसलिए क्रान्तिकारियों के लिए यह जरूरी हो गया कि रणवीर सेना को ध्वस्त करने के साथ-साथ इन पुलिस कैम्पों को भी उड़ाया जाए। पार्टी की मगध डिवीजनल कमेटी के फैसले के अनुसार पीजीए योद्धाओं ने लोदिपुर पर हमले की योजना तैयार की। इस हमले के दो लक्ष्य थे – एक यह कि पुलिस के हथियार छीनकर पीजीए को मजबूत बनाना और दूसरा यह कि पुलिस-रणवीर सेना की सांठगांठ को तहस-नहस करना। 18 मार्च की रात होली का त्यौहार मनाया जा रहा था। करीब 60 जन सैनिकों ने, जिनमें जन मिलिशिया सदस्य भी काफी संख्या में शामिल थे, ठीक 11 बजे कैम्प को घेर लिया और ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। गोलियों की आवाज सुनते ही मौबाजार चौकी से, जो सिर्फ डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर थी, पुलिस वालों ने लोदिपुर कैम्प की मदद करने की कोशिश की। लेकिन ज्यों ही वे वहां से निकले, पीजीए की एक और टुकड़ी ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। एक क्लेमोर का विस्फोट भी कर दिया जिससे वे दुम दबाकर भाग खड़े हुए।

इधर पुलिस वालों को पीजीए द्वारा लगातार चेताया जा रहा था कि वे हथियार डाल दें। उन्होंने पुलिस को आश्वस्त किया कि उन्हें हथियार डालने पर कुछ नहीं होगा। उन्होंने करीब एक माह पहले हुए बारा हमले की भी याद दिलाई। जब पुलिस वाले अपनी सुरक्षा के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो गए, तभी उन्होंने हथियार डालना शुरू किया। यह पूरी कार्यवाही सिर्फ 25 मिनटों में पूरी हो गई। यहां पर भी, पीजीए ने घायल पुलिस जवानों का इलाज किया और उनकी सारी रायफलें छीन लीं। इसमें पीजीए को कुल 15 .303 रायफलें और 800 गोलियां मिल गईं।

मजे की बात यह है कि यह हमला जब शुरू हुआ गांव के लोगों को सहसा यह समझ में नहीं आया कि हमला कौन कर रहा था। लेकिन क्रान्तिकारियों द्वारा पुलिस को दी जा रही चेतावनियों को सुनकर वे समझ गए कि यह पीपुल्सवार का हमला है। तब गांव की उत्पीड़ित जनता ने रणवीर सेना और पुलिस के विरोध में नारे लगाना शुरू किया। बाद में पीजीए सैनिकों ने जनता को बताया कि प्रतिक्रियावाद को खत्म करना है तो पीपुल्सवार और एमसीसीआइ की अगुवाई में जारी जनयुद्ध में शामिल हों। ❑

क्रांतिकारी कतारों और जनता के समक्ष

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] और एमसीसीआई की संयुक्त आत्मालोचना और आह्वान

कामरेडो और दोस्तो!

सामन्तवाद व साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकते हुए, नव जनवादी भारत के निर्माण हेतु दीर्घकालीन लोकयुद्ध के तहत सशस्त्र कृषि क्रांति, जन फौज व आधार क्षेत्र निर्माण के रास्ते पर सतत् बढ़ने वाले दो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठन भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] और एमसीसीआई को आप सभी भली-भांति जानते हैं। यद्यपि हम दोनों संगठनों का उद्‌भव व विकास का इतिहास अलग-अलग है, किन्तु, एक लक्ष्य व दिशा पर कामकाज आगे बढ़ाने की वजह से दोनों संगठनों का आपसी रिश्ता आरम्भ से ही सौहार्दपूर्ण व भाईचारात्मक रहा है। हम दोनों संगठनों के विचारों, सिद्धान्तों, नीतियों व कार्यक्रमों में एकता ही प्रधान बिन्दु रहा है, जो स्वाभाविक भी है। फिर, कुछ मतभेद के बिन्दु भी रहे हैं। हम दोनों संगठनों का लक्ष्य मतभेद के मूल-मूल बिन्दुओं को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल करते हुए, एक अखिल भारतीय पार्टी बनाने का रहा, और इस उद्देश्य से 1981 से ही एकता वार्ता जारी रही है। लेकिन 1995 में कुछ महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक व राजनीतिक बिन्दुओं पर मतभेद उभर आने की वजह से एकता वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया, जिसकी वजह से द्विपक्षीय वार्ता कुछ समय के लिए बाधित रही।

फिर भाकपा (मा-ले) [पार्टी यूनिटी] और एमसीसी का भी आरम्भिक हतिहास बड़ा ही सौहार्दपूर्ण, भाईचारात्मक व सहयोगपूर्ण ही था। किन्तु, बाद में दोनों संगठनों के बीच इलाके में कामकाज के दौरान कुछ समस्याएं उभर आई, और वह संघर्ष एक-दूसरे के बीच हथियारी झड़प तक पहुंच गया, और हथियारी झड़प एक बार शुरू हो गया तो कई सालों तक चली। निश्चय ही यह अनपेक्षित, दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण दौर था, परन्तु कड़वी सचाई थी। और, पार्टी यूनिटी, पीपुल्सवार दोनों का एक नई पार्टी भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] में विलय होने के बाद यह झड़प पीपुल्सवार और एमसीसी के बीच के संघर्ष में बदल गई।

इस आपसी संघर्ष में दोनों पक्षों के बहुत सारे नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की प्राणहानि तथा अपार शारीरिक व आर्थिक क्षति हुई, जो अन्ततः भारतीय क्रांति को ही एक भारी नुकसान पहुंचाई है। इस पर दोनों संगठनों के भीतर आतंरिक बहस शुरू हो गई और अन्ततः यह महसूस किया गया कि यह गैर-सर्वहारा रुझानों की अभिव्यक्ति है, तथा क्रांति के इतिहास में एक काला अध्याय है, इसे जितना जल्द सम्भव हो बन्द करना आवश्यक है। अतएव 2000 में एमसीसी तथा भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार], दोनों पार्टियों ने अपने-अपने तरफ से झड़प बन्द करने की घोषणा की, और उसके साथ ही हथियारी संघर्ष रुकने की प्रक्रिया शुरू हुई।

इसके बाद अगस्त '01 में पुनः भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] तथा एमसीसी के केन्द्रीय प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, दोनों संगठनों के अतीत का मूल्यांकन करते हुए, आत्मग्लानी के साथ भारतीय क्रांति में हुए इस नुकसान के लिए आलोचना व आत्मालोचना करते हुए एक संयुक्त आह्वान करके दोनों कतारों को ही झड़प दृढ़ता से बन्द करने और संयम व शान्ति बनाए रखते हुए, आपस में बातचीत के जरिए तमाम विरोधों को हल करने की अपील की। यह बैठक दोनों संगठनों के बीच पुनः सौहार्दपूर्ण व भाईचारात्मक संबन्ध का नया अध्याय शुरू करने हेतु मील का पत्थर बनी। उसके बाद दोनों संगठनों के सम्बन्ध काफी अच्छे होने लगे, तथा उसके बाद की द्विपक्षीय बैठकों से कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त कार्यक्रमों का भी आरम्भ हुआ। साथ-साथ पुनः सैद्धान्तिक-राजनीतिक व सांगठनिक मत विरोध के बिन्दुओं पर वार्ता का निर्णय हुआ।

दोनों के बीच के आपसी सम्बन्धों में लगातार सुधार आने की सिलसिलेवार प्रक्रिया के तहत ही, फिलहाल हुई एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय केन्द्रीय बैठक के दौरान दोनों संगठनों ने आपस में बहुत सारे सैद्धान्तिक-राजनीतिक और अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय मुद्दों पर एकरूपता तो स्थापित कर ही ली, साथ-साथ दोनों के बीच एकता बनाने का आधार भी मजबूत करने में सक्षम हुए। खासकर दोनों संगठनों ने अपना सैद्धान्तिक आधार के बतौर मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद को ग्रहण किया है। दोनों संगठनों ने ही इसी सैद्धान्तिक आधार के आलोक में सारी समस्याओं को हल करने की शपथ ली है।

ऐसी स्थिति में पुरानी गलतियों का कारण ढूंढ निकालने में और गलतियों से सम्बन्धित अपनी-अपनी कमियों को समझते हुए दोनों संगठनों ने दोनों पार्टीयों के तमाम कतार और क्रांतिकारी जनता के पास अपनी कमियों के बारे में खुले रूप से आत्मालोचना प्रस्तुत करने का निर्णय किया है। हम दोनों संगठन दोनों पक्ष से मारे गए तमाम साथियों को महान शहीद के रूप में मानते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते कर रहे हैं, तथा सभी शोक संतप्त परिवारों व सम्बन्धियों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट करते हैं। साथ ही साथ, दोनों सगंठन पिछली गलतियों का तमाम जिम्मा स्वीकारते हुए, अपने-अपने लम्बे पेटीबुर्जुआ तथा बुर्जुआ चिन्तन के खिलाफ तीव्र संघर्ष चलाने के प्रति सदा गम्भीर रहने को अंगीकार करते हैं, और इसके लिए फिर एक बार मार्क्सवादी पद्धति के जरिए सारी समस्याओं का हल न कर पाने के चलते भारतीय क्रांति को हुई इस अपार क्षति के लिए आत्मालोचना कर रहे हैं।

जो भी हो, देर से ही सही, एक सही निर्णय पर पहुंच जाने और इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय क्षेत्र के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों, ग्रुपों व व्यापक क्रांतिकारी व जनवादी जन-जनसमुदाय का भारी सहयोग के प्रति हम दोनों संगठन धन्यवाद प्रक्ट करते हैं। साथ-साथ, आज की कठिन व जटिल परिस्थिति में जनता के दुश्मन, साम्राज्यवाद, दलाल पूंजीवाद एवं सामन्तवाद तथा उसकी रक्षा व विकास में तैनात भारतीय राज्यंत्र का क्रांतिविरोधी, बर्बर घेराव-दमन व अत्याचार का मुकाबला करते हुए क्रांति की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए दोनों संगठन क्रांति के तीन जादुई हथियार – एक अखिल भारतीय मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी पार्टी तथा जनसेना व संयुक्त मोर्चा – निर्माण करने के लक्ष्य में जारी प्रयासों को सफ्ल बनाने हेतु मजदूर, किसान, छात्र-नौजवान, बुद्धिजीवी, महिलाओं समेत तमाम राष्ट्रीयताओं के मेहनतकश व प्रगतिशील जन समुदाय को आगे आने की अपील करते हैं।

दिनांक : 17-2-2003 ***क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ***

केन्द्रीय कमेटी	**केन्द्रीय कमेटी**
भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]	**एमसीसीआई**